Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

हिन्दी दैनिक

E-Mail : mantragwalior@gmail.com

संस्करण : ग्वालियर
वर्ष : 03
अंक : 158
पृष्ठ : 6
मूल्य : 2.00
बुधवार,07 जनवरी 2026

मंत्र भारत

ग्वालियर, मुम्बई, लखनऊ एवं प्रयागराज,से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 जमीन से आसमान तक कोहरे का पहरा

4 पाकिस्तान को लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं अब बदल रही

5 दीपिका ने फैंस के साथ मनाया जन्मदिन, दिए कीमती तोहफे

मनरेगा बनाम वीबी-जी रामजी पर बोले सीएम

पहले डाका डाला अब मील का पत्थर बनेगा

कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर किया प्रहार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने जी राम जी कानून पर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जीरामजी की खूबी गिनाईं। सीएम योगी ने कहा कि जीरामजी में रोजगार की गारंटी है। वीबी-जी राम जी से पार्दिशता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस पार्टी और उनका INDIA गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून (VB-G RAM G एक्ट) को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। यह हैरानी की बात है कि देश के हित में, मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास के लिए उठाए गए इस अहम कदम का समर्थन और स्वागत करने के बजाय- जिसके लिए INDIA गठबंधन को प्रधानमंत्री और NDA का आभार व्यक्त करना चाहिए था, वे खुलेआम अपनी पुरानी भ्रष्ट प्रथाओं का समर्थन कर रहे हैं। अगर हम VB-G RAM G एक्ट की विशेषताओं को देखें, तो यह एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, गारंटी देने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति बनाने, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि हो,

किसानों और मजदूरों दोनों के हितों का रखा ख्याल

के लिए पारित किया गया है। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है... मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह (VB-G RAM G एक्ट) विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब राज्य विकसित हों। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी बुनियादी इकाई, यानी गांव, विकसित होगा। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, तभी विकसित भारत का सपना आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि पहले श्रमिकों के हक पर डाका डाला जाता था। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। हर जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत थी। अब मजदूरों को समय पर भुगतान होगा। अब हाजिरी भरने की औपचारिकता नहीं होगी। ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। सीएम योगी बोले- अधिनियम आपको एक गारंटी दे रहा सीएम योगी ने कहा, अब इस वर्ष विकसित भारत की रामजी की इस स्कीम के माध्यम से अधिनियम आपको एक गारंटी दे रहा है। टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति से जीयोटेगिंग, सैटेलाइट इमेजनेरी, रियल-टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और यह इस्टोर का भी इस्तेमाल हो सकता है। सीधे डिजिटल भुगतान डीबीटी के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेज देंगे। यह उसके माध्यम से होगा फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद है आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में शोर-शब्बर में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था।

सीएम धामी ने कही ये बात

अंकिता के पिता से बात करूंगा, हम हर जांच के लिए हैं तैयार'

देहरादून, (एजेंसी): उत्तराखंड में इन दिनों गरमाए मुद्दों के बीच सीएम धामी ने आज प्रेसकांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अंकिता मामले में सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता के पिता से बात करूंगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या एक संवेदनशील व हृदय विदारक घटना है। प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की मजबूती से पैरवी की और तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। आज मंगलवार को सचिवालय मीडिया हाउस में पत्रकारों से वार्ता में सीएम धामी ने कहा कि हाल ही में जारी एक ऑडियो की सत्यता जानने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार इस मामले में हर जांच करने के लिए तैयार है। कोई भी दोषी होगा वह छूटेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा अंकिता के माता पिता से बात करेंगे और वह जो चाहेंगे सरकार उस पर निर्णय लेगी। वायरल ऑडियो के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित अंकिता के परिजन हुए हैं। तीन साल बाद फिर गरमाया मामला प्रदेश में इन दिनों गरमाए मुद्दों के बीच सीएम धामी ने प्रेसकांफ्रेंस की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरे हैं। तीन साल पहले हुए चर्चित अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम सामने आने पर विपक्ष सहित तमाम सामाजिक संगठन सरकार से सीबीआइ जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

सार संक्षेप

सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को यहां सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत ठीक है और उन्हें छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल के एक सूत्र ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि नियमित जांच के तहत उन्हें भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता को काफी समय से खांसी की समस्या है और वह समय-समय पर, खासकर शहर में प्रदूषण के कारण जांच के लिए आती रहती हैं। सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी ने दिसंबर 2025 में ही अपना 79वां जन्मदिन मनाया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन

पुणे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के पुणे में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। कलमाड़ी के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने करीब तीन बजकर 30 मिनट पर अंतिम सांस ली। वह रेल मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री रहे थे और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी थीं। पुणे की प्रमुख राजनीतिक हस्ती कलमाड़ी ने लोकसभा में कई बार इस शहर का प्रतिनिधित्व किया। अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले और वह कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रशासन से जुड़े रहे। उनके निधन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया।

दिल्ली विधानसभा में कुत्तों के मुद्दे पर हंगामा

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को लंच तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा है। बीजेपी नेताओं ने सदन के अंदर अरविंद केजरीवाल माफी मांगो के नारे लगाए जिससे विधानसभा के अंदर माहौल गरमा गया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद समेत तमाम विधायकों का कहना है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कुत्तों की गिनती के लिए सरकारी टीचरों की नियुक्ति को लेकर झूठ फैलाया और ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा शुरू होने से पहले ही कुत्तों की गिनती के लिए सरकारी टीचरों वाले मामले पर बात की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सीएक्यूएम को लगाई फटकार

कर्तव्य निभाने में रहे असफल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में जारी वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। जिसमें शीर्ष अदालत ने दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने की मोहलत मांगने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कर्तव्य निभाने में असफल रहने पर फटकार लगाई है। वहीं सीएक्यूएम की दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने की मांग को ठुकरा दिया है। सीएक्यूएम को 'सुप्रीम' फटकार मंगलवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने का समय मांगा था। जिस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि आयोग अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। वहीं अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न हितधारक के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर विचार करेगा। इसी के साथ दो हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य कारणों पर रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आयोग को दो हफ्ते में एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाने और बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या आप प्रदूषण के कारणों की पहचान कर पाए हैं? इन सभी दिनों में बहुत सारा मटेरियल पब्लिक डोमेन में आ रहा है, एक्सपर्ट्स आर्टिकल लिख रहे हैं, लोगों की राय है, वे हमें मेल पर भेजते रहते हैं। टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश पीठ ने आगे कहा कि भारी वाहन इसमें (वायु प्रदूषण) बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसलिए पहला सवाल यह है कि हम इससे कैसे निपटें। 2 जनवरी को मीटिंग करके और हमें यह बताना कि हम दो महीने बाद आएंगे, यह हमें मंजूर नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने और विभिन्न हितधारक के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर कानूनी सख्ती बढ़ी

नईदिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि कि कामुक इरादे से किसी छोटे बच्चे को अपने गुप्तांगों को छूने के लिए मजबूर करना बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत गंभीर यौन हमला है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने लगभग चार साल की बच्ची के सामने अपने गुप्तांग को प्रदर्शित करने और उसे छूने के लिए मजबूर करने पर पोक्सो अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दोषी करार दिये जाने और सजा सुनाये जाने को चुनौती दी थी। पोक्सो के तहत बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करना गंभीर यौन हमले की श्रेणी में आता है। अपीलकर्ता को निचली अदालत ने जुलाई 2024 में दोषी ठहराया था और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वह (अपीलकर्ता) पीड़िता के घर में किरायेदार था। यह अपराध 2022 में हुआ था। उच्च न्यायालय ने कहा, कामुक इरादे से किसी छोटे बच्चे को गुप्तांग छूने के लिए मजबूर करना गंभीर यौन हमला है। इसलिए पोक्सो कानून अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध सिद्ध होता है। उच्च न्यायालय ने पांच जनवरी को अपने फैसले में कहा, अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे लंबित आवेदनों (यदि कोई हों) के साथ खारिज किया जाता है। उच्च न्यायालय ने आरोपी के इस दावे को खारिज कर दिया कि पीड़िता को सिखा-पढ़ा दिया गया है और उसके (आरोपी के) विरूद्ध अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन उत्पीड़न का मूल आरोप पीड़िता के बयानों में लगातार बना रहा और अभिव्यक्ति में मामूली बदलावों से उसकी विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

जींद से सोनीपत, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन होगा शुरू

चंडीगढ़, (एजेंसी)। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा में शुरू होने वाली है। हरियाणा सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि उत्तरी रेलवे की यह महत्वाकांक्षी परियोजना अंतिम चरण में है जिसके तहत जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। जींद में स्थापित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए 11 केवी की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। यह संयंत्र ट्रेन के नियमित संचालन के दौरान ईंधन प्रदान करेगा। इस परियोजना के लिए स्थापित हाइड्रोजन संयंत्र की भंडारण क्षमता 3,000 किलोग्राम है और यह अब चालू होने के अंतिम चरण में है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

(डीएचबीवीएन) के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की समीक्षा की और निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए। पिछले महीने, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित बयान में कहा था कि भारतीय रेलवे ने प्रायोगिक तौर पर अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए एक अत्याधुनिक परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा था, हाइड्रोजन ट्रेन-सेट का निर्माण पूरा हो चुका है। इस ट्रेन-सेट में उपयोग के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध कराने हेतु जींद में एक हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन का एक प्रमुख तत्व है।

भ्रष्टाचारा, वंशवाद से हिंदू -विरोध तक, गृह मंत्री के 5 बड़े आरोपों से घिरी डीएमके सरकार

तमिलनाडु, (एजेंसी): भाजपा नेता एएनएस प्रसाद के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति, हिंदू विरोधी होने, दमन और केंद्रीय फंड पर गुमराह करने के पांच गंभीर आरोप लगाए हैं, इसे देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर सिर्फ अपने बेटे उदयनिधि को सीएम बनाने का लक्ष्य रखने और प्रदर्शनकारियों के दमन का भी आरोप लगाया।

भाजपा नेता एएनएस प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके सरकार और

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार, दमन, वंशवादी राजनीति, हिंदू विरोधी होने और केंद्रीय निधियों के बारे में जनता को गुमराह करने के पांच गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन आरोपों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। भाजपा नेता ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई तीखी आलोचना का हवाला देते हुए उनके हालिया बयान को भी याद किया, जिसमें उन्होंने डीएमके सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया था। 4 जनवरी को पुदुक्कोट्टई में एक जनसभा में शाह ने डीएमके पर तीखा हमला करते हुए कहा, डीएमके सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। क्या द्रविड़ मॉडल की यह सरकार, जो तमिलनाडु में किसी भी काम के लिए 20% कमीशन मांगती है, TASMAC के राजस्व और ऋणों पर निर्भर रहकर राज्य को पतन की ओर ले जा रही है, जनहितैषी राजनीति है? शाह ने आगे सवाल किया, क्या यह उचित है कि सफाईकर्मियों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, किसानों और अन्य विरोध प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर हिंसा की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए? गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार और बड़े घोटालों में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री स्टालिन का एकमात्र लक्ष्य उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है!

गोयल ने कंपनियों से सीएसआर खर्च को कुपोषण से निपटने पर लगाने का अनुरोध किया

नईदिल्ली, (एजेंसी)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कॉरपोरेट जगत से अपने सीएसआर खर्च को कुपोषण से निपटने में लगाने का मंगलवार को आह्वान किया और इसे भारत के भविष्य एवं उनके अपने व्यावसायिक हितों के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। एनडीडीबी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ह्यपोषण सुरक्षा एवं कुपोषण निवारण में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिकाश विषय पर राष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को कुपोषण-मुक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, देश को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गर्भावस्था और शिशु के विकास के चरण में ही कुपोषण को रोका जा सकता है। मंत्री ने इस क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यों की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए यह बात कही। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि कुपोषण की रोकथाम पर केंद्रित सीएसआर गतिविधियों से निवेश पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, यह दान नहीं है, आप अपनी कंपनी के भविष्य के मुनाफे में निवेश कर रहे हैं। अगर आप अपनी गतिविधियों को कुपोषण से जोड़ते हैं तो आप अपना ही भला कर रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियां खुद की मदद कर रही हैं, नए बाजार, नया श्रम, नए कर्मचारी एवं भविष्य के नए उपभोक्ता तैयार कर रही हैं। गोयल ने कंपनियों से आग्रह किया कि वे दो प्रतिशत सीएसआर खर्च के अनिवार्य नियम को बाध्यकारी दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें।

ईसी ने जारी की यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची

एसआईआर के बाद 12.55 करोड़ वोटर, 2.89 करोड़ के कटे नाम

लखनऊ,(संवाददाता)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जिसमें लगभग 28.9 मिलियन (2.89 करोड़) नाम हटा दिये गये हैं। अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ हो गई है, जो लगभग 18.70 प्रतिशत की कमी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रति बूथ 1500 से 1200 वोटर्स के हिसाब से पोलिंग बूथ को तर्कसंगत बनाने के बाद, अब राज्य में 15030 नए बूथ जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 1,62,486 से बढ़कर 1,77,516 हो जाएगी। 23 दिसंबर को ईसीआई ने प्रदेश के 75 जिलों में 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक 1,200 मतदाताओं के आधार पर पोलिंग स्टेशनों के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11 दिसंबर के डेटा के अनुसार, जब गिनती के दूसरे दौर का समापन हुआ था, तो राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 2.96 करोड़ थी, जिनका पता नहीं चल पाया था। गिनती के तीसरे दौर के बाद 26 दिसंबर के डेटा के अनुसार, यह आंकड़ा घटकर 2.89 करोड़ वोटर्स हो गया। आंकड़ों के अनुसार, 28.9 मिलियन ऐसे वोटर्स में से जिनका पता नहीं चल पाया था, उनके 12.9 मिलियन (8.40 प्रतिशत) को स्थायी रूप से स्थानांतरित, 4.6 मिलियन (2.99 प्रतिशत) को मृत, 2.54 मिलियन (1.65 प्रतिशत) को डुप्लीकेट और 7.95 मिलियन (5.15 प्रतिशत) को लापता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 774,472 अन्य वोटर्स (0.50 प्रतिशत) ने बूथ-स्तरीय अधिकारियों से फॉर्म लेने के बाद भी गिनती के फॉर्म वापस नहीं किए थे। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को कॉपी दे दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिणवा ने कहा कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। हमने नए पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, हमने 6 दिन का समय निर्वाचन आयोग से मांगा। 15 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने, 15 करोड़ मतदाता थे। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो यूपी की नई वोटर लिस्ट जारी की गई है, वह ड्राफ्ट लिस्ट है। अगर आप अपने नाम वाली या अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका तरीका बहुत आसान है।

भारतीय रेलवे ने आधुनिक जनरल और गैर-एसी कोचों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ आम यात्रियों के लिए किफायती यात्रा को सुदृढ़ किया है

गोरखपुरः कोशिश कर रहे बेईमान उपयोगकताओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, 5.73 करोड़ संदिग्ध और निष्क्रिय क्फ्ळड उपयोगकर्ता खातों को निष्क्रिय या अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, और आगे की कार्रवाई जारी है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए बड़े निवेश और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है यात्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और 2025-26 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) आवंटन के तहत सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का 84 प्रतिशत पहले ही उपयोग किया जा चुका है। ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है, जो 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 और 2025-26 (नवंबर 2025 तक) में और भी घटकर 11 रह गई है, जबकि 2004-14 के दौरान प्रति वर्ष औसतन 171 दुर्घटनाएँ होती थीं। चालू वित्त वर्ष में सुरक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़कर ?1,16,470 करोड़ हो गया है। कोहरे से बचाव के उपकरणों की संख्या 2014 में 90 से बढ़कर 2025 में 25,939 हो गई है। अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों की शुरूआत से नॉन-एसी और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिनमें स्लीपर और जनरल क्लास कोच सहित सभी प्रकार के नॉन-एसी कोच उपलब्ध हैं, किफायती किराए पर उच्च गुणवत्ता वाली यात्रा प्रदान कर रही हैं। 2025 के दौरान, 13 अमृत भारत ट्रेनें शुरू की गईं, जिससे कुल परिचालन सेवाओं की संख्या 30 हो गई। इसके अतिरिक्त, भुज-अहमदाबाद और जयनगर-पटना के बीच दो नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं भी चल रही हैं, जिससे उच्च आवृत्ति वाली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। वर्तमान में, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 30 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हैं, जो 15133/15134 छपरा-आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस, 15293/15294 मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 19021/19022 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस, 19623/19624 मदार जंक्शन (अजमेर)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, 14628/14627 छेहरटा (अमृतसर)-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस, 16601/16602 इरोड जंक्शन -जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस, 13697/13698 गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 14048/14047 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस, 22361/22362 राजेंद्र नगर (टी) - नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस, 15561/15562 दरभंगा-गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, 13435/13436 मालदा टाउन-गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, 11015/11016 लोकमान्य तिलक(टी) -सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस, 13434/13433 मालदा टाउन - एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, 15557/15558 दरभंगा जं. - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। भारतीय रेलवे किफायती नॉन-एसी ट्रेनों की क्षमता बढ़ाकर, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाकर और स्टेशन सुविधाओं में सुधार करके आम यात्रियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अवैध टिकटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सुरक्षा में बड़े निवेश और नॉन-एसी अमृत भारत ट्रेनों की शुरूआत तथा बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ, भारतीय रेलवे लगातार एक आधुनिक, समावेशी और यात्री-केंद्रित परिवहन प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो रोजमर्रा के यात्रियों पर केंद्रित है।

232 पर इंजीनियरिंग कार्य किये जाने के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण निम्नवत रहेगा

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालनिक सुगमता हेतु उत्तर रेलवे के जम्मूतवी मंडल पर कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-17, शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर-चक रखवाल स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-163 तथा पठानकोट कैंट-कंद्रोरी स्टेशनों के मध्य पुल सख्या-137 एवं 232 पर इंजीनियरिंग कार्य किये जाने के कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण निम्नवत रहेगा।

निरस्तीकरण-

-काठगोदाम से 31 मार्च, 2026 तक चलने वाली 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

-जम्मूतवी से 29 मार्च, 2026 तक चलने वाली 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

-कानपुर सेंट्रल से 31 मार्च, 2026 तक चलने वाली 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

-काठगोदाम से 30 मार्च, 2026 तक चलने वाली 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

-गाजीपुर सिटी से 27 मार्च, 2026 तक चलने वाली 14611 गाजीपुर सिटी-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

-श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 26 मार्च, 2026 तक चलने वाली 14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

आधुनिक डिजिटल वॉकी-टॉकी सेट के उपयोग से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी एवं रेल संचलन में सुविधा होगी तथा रेल संरक्षा और मजबूत होगी

गोरखपुर : रेलवे द्वारा संरक्षा को सुदृढ़ करने एवं रेलवे परिचालन को सुगम बनाने के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों में नई तकनीकी का समावेश कर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे पर 1525 आधुनिक एवं उन्नत डिजिटल वॉकी-टॉकी का प्रावधान किया गया है। जिसमें 845 डिजिटल वॉकी-टॉकी सेट ड्राईवर एवं गार्ड (क्रू कर्मी) उपयोग कर रहे है तथा 680 सेट क्रू कर्मियों के अतिरिक्त रेल संचलन के क्षेत्र में कार्यरत अन्य रेलकर्मी उपयोग कर रहे हैं। उन्नत व आधुनिक डिजिटल वॉकी-टॉकी सेट में बेहतर स्पीच क्वालिटी होती है, जिसकी रेंज पुराने वाकी टॉकी से ज्यादा है तथा इसका बैटरी बैक-अप भी बेहतर है। इस आधुनिक वॉकी-टॉकी की प्रोग्रामिंग एनालॉग एवं डिजिटल दोनों फ्रिक्वेंसी पर किया गया है, जिससे इसकी क्षमता पहले उपयोग की जाने वाली (एनालॉग) वॉकी-टॉकी की अपेक्षा दोगुना है। इसका उपयोग वॉइस एवं डाटा दोनों कम्यूनिकेशन के लिए होता है, जिससें डाटा रिकार्ड की जा सकती है। जबकी पुराने वॉकी टॉकी केवल वॉइस कम्यूनिकेशन के लिए ही उपयोग होता था। इसमें अधिकतम 16 चैनल की क्षमता है, जिससे एक समय में 16 चैनलों (स्थानों) पर कम्यूनिकेशन कर सकते है, जबकी पुराने वॉकी-टॉकी में 08 चैनल ही उपलब्ध थे। आधुनिक डिजिटल वॉकी-टॉकी सेट के उपयोग से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी एवं रेल संचलन में सुविधा होगी तथा रेल संरक्षा और मजबूत होगी।

वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरे तिमाही तक पूर्वोत्तर रेलवे को माल लदान से रू. 360 करोड़ से अधिक की आय

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा व्यापारियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जा रही उन्नत सुविधाओं तथा मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिटों के सुनियोजित प्रयासों से पूर्वोत्तर रेलवे पर माल लदान में वृद्धि का क्रम जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरे तिमाही में माह दिसम्बर, 2025 तक कुल 3.247 मिलियन टन माल लदान हुआ, जिससे रू. 360.81 करोड़ की आय हुई है तथा माह दिसम्बर, 2025 में कुल 0.307 मिलियन टन माल का लदान हुआ, जिससे रू. 37.043 करोड़ की आय हुई। रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समेकित प्रयासों के फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे पर वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरे तिमाही में माह दिसम्बर, 2025 तक कुल 3.247 मिलियन टन माल लदान हुआ, जो गत वित्त वर्ष 2024-25 के तीसरे तिमाही तक कुल 3.038 मिलियन टन माल लदान की तुलना में 6.88 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 के माह दिसम्बर में कुल 0.307 मिलियन टन माल का लदान हुआ, जो गत वर्ष के माह दिसम्बर में कुल 0.289 मिलियन टन माल लदान की तुलना में 6.23 प्रतिशत अधिक है।

मध्य रेलवे के उरुली स्टेशन पर 01 मिनट का अस्थाई ठहराव निम्नवत प्रदान किया जायेगा

गोरखपुरः रेलवे प्रशासन द्वारा श्री प्रयागधाम, उरुली में वार्षिक भंडारा उत्सव में जाने वाले श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा हेतु निम्नलिखित गाड़ियों का मध्य रेलवे के उरुली स्टेशन पर 01 मिनट का अस्थाई ठहराव निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

अस्थाई ठहराव-

-15030 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस 17 जनवरी, 2026 को उरुली स्टेशन पर 11.35 बजे पहुँचकर 11.36 बजे प्रस्थान करेगी।

-15029 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस 09 जनवरी, 2026 को उरुली स्टेशन पर 01.00 बजे पहुँचकर 01.01 बजे प्रस्थान करेगी।

-12104 लखनऊ जं.-पुणे एक्सप्रेस 08 जनवरी, 2026 को उरुली स्टेशन पर 16.55 बजे पहुँचकर 16.56 बजे प्रस्थान करेगी।

-11407 पुणे-लखनऊ जं. एक्सप्रेस 20 जनवरी, 2026 को उरुली स्टेशन पर 22.15 बजे पहुँचकर 22.16 बजे प्रस्थान करेगी।

-11408 लखनऊ जं.-पुणे एक्सप्रेस 09 जनवरी, 2026 को उरुली स्टेशन पर 10.00 बजे पहुँचकर 10.01 बजे प्रस्थान करेगी।

माघ में मकर संक्रांति मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा के स्नान

वाराणसी। माघ मास में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा के स्नान पड़ रहे हैं। वहीं सनातन के इस पवित्र मास में 17 व्रत और त्योहार पड़ेंगे। इस महीने में स्नान दान को विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में माघ मास की अनंत महिमा है। इस मास में भगवान श्रीविष्णु, सूर्यदेव और मां गंगा की पूजा आराधना का विशेष फल मिलता है। तीर्थों में स्नान, दान-पुण्य और आराध्य देवों की पूजा को फलदायी माना गया है। इस मास में पवित्र स्नान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के स्नान पड़ेंगे। स्नान तिथियों के अलावा 17 व्रत और त्योहार पड़ेंगे। सनातनी पंचांग के अनुसार 11वां महीना माघ है। मान्यता है कि इस मास में स्नान-दान, देवी-देवता की पूजा का अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस मास में माघ महीने में प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी, नासिक, उज्जैन जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान-दान करने और प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवास करने की मान्यता है। पंचांगों के अनुसार माघ मास की शुरूआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हुआ। जबकि इस मास का पहला स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इसके बाद मौनी अमावस्या 18 जनवरी, वसंत

पंचमी 23 जनवरी, माघी पूर्णिमा स्नान 31 जनवरी को पड़ेगा। मान्यता है कि माघ मास में सूर्यदेव की पूजा-आराधना करने से जीवन में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसी माह में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। ये हैं व्रत व त्योहार माघ मास के प्रमुख व्रत और त्योहारों में संकष्ठी श्रीगणेश चतुर्थी छह जनवरी, मकर संक्रांति व पत्तिला एकादशी 14 जनवरी, तिल द्वादशी 15 को, मास शिवरात्रि व्रत 16 को, मौनी अमावस्या 18 को, गौरी तृतीया 21 को, वरद विनायक श्रीगणेश चतुर्थी 22 को, वसंत पंचमी 23 को, अचला सप्तमी 25 को, दुर्गा अष्टमी 26 को, महानंदा नवमी 27 को, जया एकादशी 29 को, भीष्म द्वादशी 22 को, प्रदोष व्रत 30 को, माघी पूर्णिमा 31 जनवरी को पड़ेगी। सूर्यदेव को जल दें और करें तिल, गुड़ व कंबल दान माघ माह में सूर्य उपासना से मनोकामना पूर्ण होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देव को जल देना चाहिए। इस मास में विशेष तिथियों पर निराहार व्रत करने चाहिए। नियम-संयम से रहने पर भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। गीता पाठ का भी महत्व है। भगवान श्रीकृष्ण की कृपा होती है। माहभर जल में तिल डालकर स्नान करने, तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। तिल, आंवला से बनी चीजों का दान, गुड़, कंबल दान और सेवन करना लाभदायक होता है।

बम से उड़ाने की धमकी पर खंगाली गई काशी एक्सप्रेस

मऊ। काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सतर्क हुआ। मऊ स्टेशन पर

ट्रेन को पूरी तरह खाली कराकर चेकिंग की गई। मऊ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब काशी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही गोरखपुर से वाराणसी तक रेलवे और पुलिस विभाग में खलबली मच गई। ट्रेन को मऊ जंक्शन पर रोककर यात्रियों को उतारकर दो घंटे तक चेकिंग की गई। क्या है पूरा मामला काशी एक्सप्रेस (15018) रोज सुबह गोरखपुर से चलकर मुंबई लोकमान्य तिलक तक जाती है। मंगलवार की सुबह 5:53 बजे ट्रेन गोरखपुर से यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इसी बीच इंटरनेट के माध्यम से किसी ने ट्रेन में बम होने की सूचना दी। ट्रेन 9:32 बजे मऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही मऊ एसपी इलामारन जी, एएसपी अनूप कुमार, आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह, जीआरपी थानाध्यक्ष राजकपूर सिंह बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम के साथ मौजूद थे। ट्रेन रुकते ही यात्रियों को बाहर निकालकर चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ, लेकिन उसमें विस्फोटक जैसा कुछ नहीं था। रेलवे की टेक्निकल टीम ने भी अपने अनुसार बेग की चेकिंग की। इस दौरान मऊ जंक्शन के बाहर तैनात की गई थी। एसपी इलामारन जी ने बताया कि यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालकर चेकिंग की गई है, लेकिन विस्फोटक जैसा कुछ मिला नहीं है। गलत सूचना देने वाले की तलाश की जा रही है। काशी एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के बाद सुरक्षाकर्मियों ने सभी यात्रियों को बोगी के गेट के सामने लाइन लगाकर दोबारा ट्रेन में प्रवेश कराया।

विवाद में बीच-बचाव करने आए भाई-मां पर झोंका फायर

कानपुर। जाजमऊ के ताड़बगिया में विवाहिता के ससुराल वालों ने उसके भाई और मां पर फायरिंग कर दी। हालांकि, गोली ई-रिक्शे में लगी, जिससे दोनों बाल-बाल बचे। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताड़बगिया इलाके में मंगलवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। विवाहिता के साथ हो रही मारपीट की सूचना पर पहुंचे उसके भाई और मां को जान से मारने की कोशिश की गई। नकाबपोश हमलावरों ने उस समय गोली चलाई, जब पीड़ित पक्ष घर वापस लौट रहा था। इसमें महिला के मायके पक्ष के लोग बाल-बाल बच गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।

साथ ही, मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार, उन्नाव के अखलाक नगर निवासी मोहर्रम अली उर्फ राजू ने अपनी बहन का विवाह चार साल पहले ताड़बगिया के गोलू से किया था। राजू का कहना है कि गोलू मुंबई में नौकरी करता है, लेकिन उसके ससुराल वाले लगातार बहन को प्रताड़ित करते हैं। मंगलवार सुबह भी बहन को बेरहमी से पीटा गया, जिसकी सूचना पाकर राजू अपनी मां सहदुन निशां के साथ वहां पहुंचे थे। आरोपियों की पहचान की जा रही है ससुराल पक्ष की ओर से आए युवकों में से एक ने राजू को निशाना बनाकर फायर कर दिया। गोली राजू को न लगकर सीधे ई-रिक्शे की हेडलाइट में जा लगी। गोली चलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई और आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से एक खोखा बरामद किया है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मायके और ससुराल पक्ष के बीच हुए विवाद में गोली चलने की पुष्टि हुई है। आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

नवी मुंबई के लिए नई फ्लाइट इसी माह से अहमदाबाद और पुणे के लिए भी जल्द

कानपुर। चकेरी एयरपोर्ट से इसी माह के अंत तक नवी मुंबई के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू होगी। फरवरी में अहमदाबाद और पुणे के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। कानपुर में नए साल की शुरूआत के साथ ही कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस इसी माह के अंत तक कानपुर से नवी मुंबई के लिए एक नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इस नई उड़ान के शुरू होने से यात्रियों को खासी सहूलियत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें नवी मुंबई जाने के लिए मुंबई से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और इंडिगो एयरलाइंस के बीच इस नई फ्लाइट को लेकर सहमति बन गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वर्तमान में इंडिगो की कानपुर से मुंबई के लिए रोजाना केवल एक फ्लाइट संचालित होती है। नई फ्लाइट के जुड़ने से कानपुर एयरपोर्ट पर कुल उड़ानों की संख्या पांच हो जाएगी। कानपुर एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम नवी मुंबई के अलावा, अहमदाबाद और पुणे के लिए भी फ्लाइट शुरू करने के लिए मंथन चल रहा है।

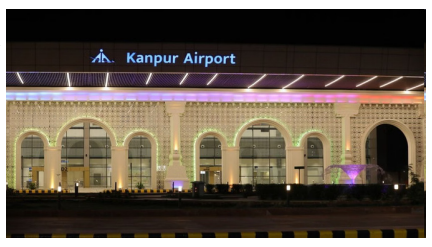

संक्षिप्त खबरें

सकट चतुर्थी आज, बाजारों में छाई रही रौनक

बस्ती। ठंड के बीच सोमवार को शहरी बाजार गुड़ की सोंधी खुशबू और तिलवा त्योहार की मिठास से गुलजार रहा। छह जनवरी को तिलवा पूजन (सकट चतुर्थी) है। ऐसे में सुबह से देर शाम तक बाजार में रौनक रही। दुकानदार घरों में गुड़ पिघलाकर तिल, लइया, मक्का, रामदाना आदि मिलाकर लड्डू व पट्टी बनाकर बाजार में लाए हैं। गंजी, गुड़ के अलावा तिल की भी बिक्री तेज दिखी। दुकानदार राकेश ने बताया कि सकट चतुर्थी के बाद मकर संक्रांति है। फरवरी माह तक तिल, लइया व रामदाना आदि से बने लड्डू की बिक्री होगी। दुकानदार देवा का कहना है कि पहले लोग घरों में ही तिल के लड्डु और तिलकुट बनाते थे, लेकिन अब बाजार में बना ताजा और शुद्ध सामान लोगों को अधिक भा रहा है। धीरे-धीरे खरीदारी करने के लिए लोग आने लगे हैं। सकट को लेकर गुड़ 60 रुपये किलो, काला तिल 320 रुपये किलो और सफेद तिल दो सौ रुपये पहुंच गया है। पूजन के लिए लाल गंजी भी 50 रुपये पाव और अन्य पूजन सामग्री महंगे बिक रहे हैं। कंपनीबाग से लेकर फौव्वारा तिराहा तक सड़क पटरी पर सजे बाजार में ग्राहक खरीदारी करते दिखे।

सभासदों ने किया बैठक का बहिष्कार

कप्तानगंज। नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक सोमवार पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में जुटे सभासदों ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बैठक से बहिष्कार किया। सभासदों ने परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। इससे नगर पंचायत कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। सभासदों ने अधिशाषी अधिकारी को पत्र देकर नगर पंचायत में सभासदों की उपेक्षा और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावों के क्रम में उनके वार्डों में काम नहीं कराए जाते, जो कार्य कराए भी जाते हैं उसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सफाई और प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था चौपट है। बार-बार मौखिक शिकायत के बावजूद कोई प्रभावशाली कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। 30 महीने में केवल छह बार ही बोर्ड की बैठक हुई है। अधिशासी अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि जो प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें 10 सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ इसलिए बैठक को स्थगित कर दिया गया है । नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि कप्तानगंज नगर पंचायत में गुणवत्तापूर्ण कार्यों के बल पर आदर्श नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है।

सिद्धार्थनगर की टीम ने महादेवा बस्ती को 70 रन से दी शिकस्त

बस्ती। शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को तीन मुकाबले खेले गए। मैच के दौरान खिलाड़ी जीत के लिए खूब मशक्कत करते नजर आए। मैच में विकेट गिरते और चौके-छक्के लगते ही दर्शक तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते दिखे। खेल का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक कप्तानगंज कवींद्र चौधरी अतुल, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती और उपजिलाधिकारी उमाकांत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मैच में प्रदेश के कई सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रवि बनारसी, राहुल सोलंकी, प्रवीण गेल, बलराम पांडेय, रंजीत यादव आदि ने भी प्रतिभाग किया और अपने खेल से दर्शकों का मनोरंजन किया। पहला मैच बांसी सिद्धार्थनगर और महादेवा बस्ती के बीच खेला गया। महादेवा टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बांसी की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित आठ ओवर में तीन विकेट खोकर 132 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें जीशान ने सर्वाधिक 51 रन की पारी खेली।

कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ना किसानों को जागरूक किया

कप्तानगंज (बस्ती)। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ के कृषि वैज्ञानिक डॉ. संजीव कुमार की टीम ने क्षेत्र की गन्ना फसलों का निरीक्षण करते हुए किसानों को जागरूक किया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहतर गन्ना पैदावार के गुर बताए। कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव कुमार, केएम शुगर मिल के निदेशक सुभाष चंद्र अग्रवाल, जीएम केन अनिल कुमार त्रिपाठी की टीम सोमवार की शाम चार बजे हरैया ब्लॉक के केशवापुर, कोदई, कप्तानगंज ब्लॉक के फरेंदा सेंगर, मरवटिया तिवारी, खोभा, बिहरा, रेहरवा, गांव में गन्ना की तैयार फसलों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों की टीम ने गन्ना किसान राम शंकर चौधरी, राहुल त्रिपाठी, ज्योति प्रकाश से मिलकर उन्हें बताया कि गन्ने की उन्नतिशील प्रजाति की बुवाई करें,समय-समय पर खरपतवार नियंत्रण करते हुए उर्वरकों का प्रयोग करें।

घर में घुसकर युवती से यौन शोषण का आरोप

बस्ती। सोनहा थानाक्षेत्र के गांव में एक युवती के साथ घर में घुसकर यौन शोषण का आरोप लगा है। थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि आठ जून को वह अपने घर पर अकेले थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी देवराज अपने तीन साथियों के साथ जबरन उसके घर के अंदर घुस गया। आरोपी देवराज डरा-धमका कर उसे जबरन कमरे में ले गया और जबरन यौन शोषण किया। विरोध करने पर अपशब्द कहते हुए पिटाई की। जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस घटना के चार दिन बाद 12 जून को आरोपी ने दोबारा घर पर आकर कमरे में आग लगा दी। मामले में न्यायालय के आदेश पर सोनहा पुलिस ने इसी थानाक्षेत्र के रहने वाले आरोपी देवराज और तीन अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो बाइकों की भिडंत में दो युवक घायल

भानपुर। सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर-रुधौली मार्ग पर परसौनिया पेट्रोल पंप के पास सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे दो बाइकों की टक्कर में दो युवक घायल हो गए।एक युवक को सिर मे गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोनहा पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचवाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, पंचम प्रसाद निवासी ग्राम बढ़या थाना सोनहा परसौनिया पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर सड़क की तरफ जैसे ही बढ़े कि उसी समय तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार मो. सउद निवासी करमहिया थाना सोनहा जनपद बस्ती की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में पंचम प्रसाद के सिर मे गंभीर चोटें आई हैं।

महिला को घर में घुसकर पीटा चार पर प्राथमिकी

पैकोलिया। थाना क्षेत्र के धोसड़े मिश्र गांव की रहने वाली महिला शेष कुमारी मिश्रा को घर में घुसकर मारने-पीटने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के धोसड़े मिश्र गांव निवासी बुद्धि सागर मिश्र की पत्नी शेष कुमारी मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोग उसके खेत में बकरी चरा रहे थे। मना किया तो नाराज होकर रीता, माधुरी और नितिन समेत चार लोगों ने शनिवार की दोपहर उसके घर में घुसकर गाली देते हुए लात, मुक्के और डंडे से पिटाई करने लगे। बेटी बचाने दौड़ी तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

टी20 वर्ल्ड कप में कौन होगा भारत का एक्स फैक्टर एबी डिविलियर्स की लिस्ट में बुमराह-अभिषेक नहीं

नई दिल्ली। एबी डिविलियर्स के मुताबिक, आगामी टी20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे निर्णायक खिलाड़ी हो सकते हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता, दबाव में प्रदर्शन और हालिया शानदार फॉर्म उन्हें भारत के लिए 'गेम चेंजर' बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने आगामी टी20 विश्व कप को लेकर टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या भारत के सबसे अहम और निर्णायक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, न कि जसप्रीत बुमराह या अभिषेक शर्मा। टीम इंडिया की गहराई ने किया प्रभावित अपने यूट्यूब चैनल 'एबी डिविलियर्स 360' पर टी20 विश्व कप की भारतीय टीम का विश्लेषण करते हुए डिविलियर्स ने कहा कि भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार संतुलन है। उन्होंने कहा, 'इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं

पुलिस की नाक के नीचे दौड़ रहे रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली

कागजों तक सीमित जिलाधीश के निर्देश: गोले का मंदिर चौराहे पर नियमों की खुलेआम उड़ाई गईं धज्जियां

■ ग्वालियर

जिले में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। खनिज विभाग द्वारा रेत के ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में पुलिस की आंखों के सामने रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली खुलेआम फर्राटा भर रहे हैं। सोमवार को शहर के सबसे व्यस्ततम गोले का मंदिर चौराहे से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली क्षमता से लगभग दोगुनी रेत भरकर गुजरी। हैरानी की

बात यह रही कि ट्रैक्टर पुलिस की मौजूदगी में निकला, लेकिन उसे रोकने या जांच करने की जहमत तक नहीं उठाई गई। जबकि उसी स्थान पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और आम वाहन चालकों के चालान काटने में व्यस्त थी। इससे साफ है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे वाहनों तक सीमित है, जबकि ओवरलोडिंग करने वाले बेखौफ हैं। इतना ही नहीं, मौके पर तैनात यातायात पुलिस के एक सिपाही ने तो ट्रैक्टर को निकलने के लिए चौराहे पर रास्ता तक दिला दिया। गौरतलब है कि जिलाधीश रुचिका चौहान ने 8 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग को पत्र लिखकर ओवरलोडिंग करने वाले ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ नियमित जांच कर सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए थे। बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं।

राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में केपी शर्मा ने जीता स्वर्ण

ग्वालियर। मध्य प्रदेश मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा में ग्वालियर के केपी शर्मा ने भाला फेंक व तस्तरी फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। साथ ही उनका चयन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भेल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, झाबुआ सहित अन्य सभी जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिसमें 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, पैदल चाल, मैराथन दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, तस्तरी फेंक आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। इस आयोजन में ग्वालियर के भारतीय दूर संचार विभाग (बीएसएनएल) से सेवानिवृत्त खिलाड़ी 75 प्लस वर्षीय केपी शर्मा ने भाला फेंक और तस्तरी फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। साथ ही फरवरी में होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए उनका चयन किया गया है। इस उपलब्धि पर प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है।

युवाओं को रोजगार के लिए कांग्रेस का मशाल जुलूस

ग्वालियर। देश और प्रदेश में बेरोजगारी एवं आए दिन युवाओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में किला गेट से घास मंडी चौराहे तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। श्री शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के वादे के कारण सत्ता में आई थी, लेकिन वादा खिलाफी से युवाओं में रोष है। आज युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। कई युवा नशे के दलदल में घुस गए हैं और कई अपना और अपने परिवार का पेट पालने के कारण अपराध कर बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ झूठे वादे हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुनेंद्र सिंह भदौरिया, नवीन भदकारिया, पिंटू राजपूत, राजेश खान, दर्शन मिश्रा, मुन्नालाल खरे, रामवतार शर्मा, सोनू राजावत, अशोक तरेटिया, महेश धनौलिया, महेश मदुरिया, मनोज शास्त्री आदि मौजूद रहे।

एलआईसी तिराहा व फूलबाग पर जाम में फंसे लोग

● शाम होते ही बिगड़ने लगते हैं हालात ● कतारों में रेंगते नजर आते हैं वाहन

■ ग्वालियर

शहर में बदतर हो चले यातायात के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। एलआईसी तिराहा और फूलबाग के आसपास शाम के समय जाम लग गया। सिलसिला यहीं नहीं रुका, देर शाम तक सिंधिया कन्या विद्यालय, नदी गेट, जयेंद्रगंज, दौलतगंज, फाल्का बाजार, राममंदिर, पाटनकर चौराहा आदि क्षेत्र में जाम लगा रहा। बेतरतीब ढंग से वाहन आमने-सामने जाम में फंस जाने के कारण सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस को जाम खोलने के लिए काफी माथापच्ची करना पड़ी।

सोमवार शाम के समय एलआईसी तिराहा से लेकर पड़ाव पुल, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक मार्ग, फूलबाग पर वाहनों की लम्बी-लम्बी कतारें लग गईं। नए आरओवी और पुराने पड़ाव पुल से बंसत विहार व मोतीमहल जलविहार की ओर जाने वाले वाहन एलआईसी तिराहे पर आकर फंस गए। वाहनों के जाम में फंसने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, एलआईसी तिराहे पर तीन ओर से वाहन आकर एक स्थान पर मिलते हैं जिस कारण यहां पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। जाम की सूचना मिलने पर पड़ाव व यातायात थाने का बल मौके पर पहुंचा और जाम में फंसे वाहनों को निकाला। एक घंटे से ज्यादा समय तक जाम के हालात बने रहे।

शार्टकट निकालने के फेर में चाट बाजार में फंसे

जब एलआईसी तिराहे पर वाहन जाम में फंस गए तो वाहन चालक जल्दी निकलने के फेर में पड़ाव से होते हुए लक्ष्मीबाई स्मारक के सामने बनी चौपाटी से निकलने के चक्कर में वहां पर जाम में फंस गए। चौपाटी से लेकर नगर निगम के संग्रहालय और जल विहार तक वाहन जाम में फंस गए।

कई स्थानों पर लगता है जाम

शहर में एलआईसी तिराहा की तरह गोला का मंदिर चौराहा, रेलवे स्टेशन, सराफा बाजार, सिटी सेंटर, गोविंदपुरी चौराहा, मुरार बारादरी चौराहा, नदीगेट, जयेन्द्रगंज, कम्पू आदि स्थान हैं जहां हर रोज लोगों को जाम की समस्या से सामना करना पड़ रहा है।

मेला में बीआईएमआर के निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र का शुभारम्भ

ग्वालियर। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला परिसर में बीआईएमआर हॉस्पिटल्स द्वारा स्थापित नि :शुल्क प्राथमिक एवं आकस्मिक चिकित्सा केंद्र का शुभारम्भ मंगलवार को किया गया। मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने फीता काटकर स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीआईएमआर के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी गोविन्द देवड़ा, उपनिदेशक वेद प्रकाश पांडेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अरुण घई, डॉ. वरुण शर्मा, क्वालिटी मैनेजर डॉ. निखिल पाठक, एचआर मैनेजर कु. पूनम, को-ऑर्डिनेटर स्वाति शाह सहित अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहा। मेला अवधि के दौरान यह स्वास्थ्य केंद्र आमजन, सैलानियों एवं व्यापारियों को नि :शुल्क प्राथमिक उपचार एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यहां मरीजों को नि :शुल्क दवाइयां दी जाएंगी, साथ ही प्रतिदिन ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की जांच भी बिना किसी शुल्क के की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र में दोपहर से रात्रि तक एक चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रहेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जा सके। गंभीर अथवा जटिल बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यकतानुसार बीआईएमआर हॉस्पिटल्स रेफर किया जाएगा। इसके लिए एम्बुलेंस सुविधा भी नि :शुल्क उपलब्ध रहेगी।

फुटपाथ पर सो रहे लोगों को पहुंचाया आश्रय स्थल

ग्वालियर। अपर आयुक्त प्रदीप तोमर, उपायुक्त अमरसत्य गुप्ता, रजनीश गुप्ता द्वारा रात में अभियान चलाते हुए खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को नजदीकी रैन बसेरे में पहुंचाया गया और उन्हें रैन बसेरे में रहने की समझाइश दी गई। उपायुक्त ने शहर में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रात्रि कालीन के समय ठंड से बचाव के लिए समझाइश देते हुए आश्रय स्थल की सुविधाओं के बारे में बताया और सभी को रैन बसेरे में भेजा गया। कार्रवाई के दौरान एनयूएलएम के सिटी मिशन मैनेजर वेद सिंह राजपूत, प्रभारी दीपक झा, सामुदायिक संगठक शुभम शर्मा मौजूद रहे।

'कायाकल्प' की टीम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण

वार्ड, ओपीडी, जांच कक्ष से लेकर किचन व लॉन्ड्री तक की देखीं व्यवस्थाएं

■ ग्वालियर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 'कायाकल्प योजना' के अंतर्गत सोमवार को जिला अस्पताल का पीयर असेसमेंट किया गया। राज्य स्तर से आई दो सदस्यीय टीम ने एक दिवसीय निरीक्षण के दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई और प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। टीम में शामिल डॉ. प्रमोद मिश्रा और डॉ. सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने सुबह से शाम तक अस्पताल परिसर में रहकर विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया।

मूल्यांकन के दौरान टीम ने पुरुष एवं महिला वार्ड, प्रसूति कक्ष, ओपीडी, जांच कक्ष, दवा वितरण केंद्र और प्रतीक्षालय की स्थिति देखी। इसके साथ ही संक्रमण नियंत्रण, बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही जांच

सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता का भी अवलोकन किया गया। सपोर्ट स्टाफ की कार्यप्रणाली, लॉन्ड्री में कपड़ों की धुलाई व स्वच्छता व्यवस्था तथा किचिन में मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई की भी जांच की गई। टीम ने निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। एक दिवसीय निरीक्षण के बाद पीयर असेसमेंट की प्राथमिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिकारियों के अनुसार इस मूल्यांकन का परिणाम करीब डेढ़ महीने बाद घोषित किया जाएगा। नियमों के अनुसार यदि जिला अस्पताल को इस पीयर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो अस्पताल फाइनल असेसमेंट के लिए पात्र होगा। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष अस्पताल ने लगभग 80 अंक हासिल किए थे। इस बार अस्पताल प्रबंधन को पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान आरएमओ डॉ. जेपीएन शर्मा, सहायक प्रबंधक डॉ. राजेश बिरथरिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

उच्च शिक्षा विभाग की नई पहल

प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन से परीक्षा तक की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी

■ ग्वालियर

उच्च शिक्षा विभाग अब विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक ओर तो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने की तैयारी की जा रही है, इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी भी समय से पहले उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग की इस पहल के तहत विद्यार्थियों को यह बताया जा रहा है कि आगामी तीन महीनों में कौन-कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उनके आवेदन की संभावित तिथि क्या होगी और परीक्षा कब आयोजित हो सकती है। इससे विद्यार्थियों को पहले से तैयारी करने और समय पर आवेदन करने में सुविधा मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस दस्तावेज के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी आवश्यक जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग का मानना है कि समय पर सूचना मिलने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और तैयारी की रणनीति बेहतर ढंग से बना सकेंगे।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह पहल खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत हैं तथा सरकारी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। इससे विद्यार्थियों को अलग- अलग स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें विश्वसनीय जानकारी सीधे विभाग की वेबसाइट से मिल सकेगी।

आगामी तीन माह में परीक्षाएं

- जनवरी : एमपीपीएससी 7 जनवरी तक आवेदन।
- एसबीआइ पीओ : जनवरी माह में आवेदन शुरू।
- यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा : 14 जनवरी से आवेदन शुरू।
- सीयूईटी पीजी :14 जनवरी से आवेदन शुरू।
- रेलवे पद ग्रुप डी : 21 जनवरी से आवेदन शुरू।
- फरवरी : यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा : 3 फरवरी तक।
- यूपीएससी आईईएस परीक्षा आवेदन : 11 फरवरी से शुरू।
- यूपीएससी आईएसएस परीक्षा आवेदन :11 फरवरी से शुरू।
- यूपीएससी सेंट्रल आर्मड फोर्सेज आवेदन : 18 फरवरी से शुरू।
- रेलवे पद ग्रुप डी : 20 फरवरी तक से आवेदन शुरू
- मार्च : एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा : संभावित मार्च माह में।
- यूपीएससी आईईएस परीक्षा आवेदन : 3 मार्च तक।
- यूपीएससी आईएसएस परीक्षा आवेदन : 3 मार्च तक।
- यूपीएससी सेंट्रल आर्मड फोर्सेज आवेदन : 10 मार्च तक।
- सीयूईटी पीजी परीक्षा : मार्च माह में।

अंतरविभागीय समन्वय बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

स्कूलों की मरम्मत गुणवत्ता व तेजी से पूरी कराएं: जिलाधीश

■ ग्वालियर

जिलाधीश रुचिका चौहान ने जिले के शासकीय स्कूलों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को पूरी गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 98 स्कूलों के लिए राज्य शासन से राशि प्राप्त हुई है, उनकी मरम्मत कार्यों की सूची विधायकों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। जिलाधीश ने बैठक में मरम्मत कार्यों का फोटो सहित प्रस्तुतिकरण भी देखा।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सीएम हेल्पलाइन, युवा दिवस 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार, एमपी ई-सेवा पोर्टल, आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया, शुद्ध पेयजल आपूर्ति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। तय किया गया कि 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन शिक्षा नगर स्कूल, हजीरा में होगा, जिसकी सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाएंगी। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधीश ने बेहतर निराकरण करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित किया तथा लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के खंड स्तरीय अन्वेषक संतोष सिंह दीवान को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। लंबित शिकायतों पर वेतन कटौती की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी शासकीय अस्पतालों एवं छात्रावासों में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने, पुराने आरओ बदलने तथा जल स्रोतों की नियमित जांच व टंकियों की सफाई पर जोर दिया। आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन पूरी तरह मैरिट के आधार पर होगा और किसी भी तरह के झांसे से बचें। साथ ही सभी अधिकारियों को एमपी ई-सेवा एप स्वयं डाउनलोड कर नागरिकों को भी प्रेरित करने के निर्देश दिए।

प्रेरणादायी पहल: सरकारी स्कूलों के बच्चों की मदद को आगे आए शासकीय सेवक

■ ग्वालियर

सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना केवल शासन की ही नहीं, बल्कि समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ जिलाधीश रुचिका चौहान की पहल पर ग्वालियर जिले में एक सराहनीय प्रयास शुरू हुआ है। जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शासकीय सेवकों ने स्वयं आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

जिला प्रशासन द्वारा शासकीय सेवकों एवं जनसहयोग से जिले के सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालयों को लकड़ी की बैंच उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधीश ने अधिकारियों से अपील की कि सभी के छोटे-छोटे योगदान से बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अपील का सकारात्मक असर तुरंत दिखाई दिया और बैठक में ही लगभग एक हजार बैंच के लिए धनराशि जुटा ली गई। जिलाधीश ने स्वयं तथा रीवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ अपने पति शैलेन्द्र सिंह चौहान की ओर से 100 बैंच के लिए राशि देने की सहमति दी। जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत एवं अपर कलेक्टर सी.बी. प्रसाद ने 51-51 बैंच, जबकि उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बनवारिया, जिले के एसडीएम एवं अन्य संयुक्त कलेक्टरों ने 50-50 बैंच के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया। इसके अतिरिक्त अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपनी क्षमता अनुसार 1 से 50 बैंच तक की राशि देने की सहमति जताई।कलेक्टर ने सभी सहयोगी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयास से जिले के सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार बैंच उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला प्रशासन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार इसके लिए लगभग ढाई करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वेंडर्स से चर्चा के बाद प्रति बैंच लागत 2250 रुपए तय की गई है।

संपादकीय

वेनेजुएला पर हमला

पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी हमले के बाद गिरफ्तार करना निस्संदेह, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। वैसे आरोप मादुरो पर लगे कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया, असहमतियों को कुचला और लाखों लोगों को निर्वासन के लिये मजबूर किया। उन पर चुनाव में धांधली और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन वैश्विक कूटनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रंप के इस दांव का लक्ष्य तानाशाही के पीड़ितों को न्याय दिलाने या इस देश की संप्रभुता की रक्षा के बजाय वेनेजुएला के समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण हासिल करना ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा सैन्य अभियान चलाकर देश से बाहर किसी शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार करना तथा वहां की सत्ता को वाशिंगटन से संचालित करना निश्चय ही साम्राज्यवादी सोच का ही पर्याय है। निस्संदेह, इस अमेरिकी निरंकुशता के गहरे भू-राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। यहां तक कि मादुरो का विरोध करने वाले अमेरिका के सहयोगी देश भी, अब मुखर होकर चेतावनी देने लगे हैं। रूस और चीन इस अमेरिकी कार्रवाई को नियम-कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये खतरा बता रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के इस घटनाक्रम ने चीन को अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर अमेरिकी आलोचना को बेअसर करने का भरपूर मौका दे दिया है। जिससे ताइवान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका के इस कृत्य ने इराक और अफगानिस्तान में हमले व सेना की तैनाती की यादें ताजा कर दी हैं। ऐसे युद्ध जो अमेरिकी आत्ममुग्धता और अति-आत्मविश्वास से शुरू हुए, लेकिन उनका समापन अपमानजनक विदाई से हुआ। लेकिन इन हमलों के बाद वे देश कभी सामान्य नहीं रह पाए। वहीं ट्रंप की यह दलील कि मादुरो को पकड़ने के लिये चलाए अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण की मंशा को ही दशार्ता है। वहीं अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सुशासन, सुरक्षा के लिये वेनेजुएला की जनता की आकांक्षाओं वाले किस नेता को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। भारत भी उन देशों में शामिल है, जिन्होंने घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। जो सही मायनों में भविष्य की वैश्विक चिंताओं के अनुरूप ही है। बहरहाल, देर-सवेर ट्रंप को अहसास होगा कि एक निरंकुश शासक को हटाना आसान है, लेकिन उस देश में दीर्घकालिक शांति-स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का कोई कानूनी आधार नहीं है

> । मादुरो पर 2020 में नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अभियोग लगाया गया था। लेकिन मजे की बात है कि मादुरो की पत्नी सेलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और संशोधित अभियोग का हिस्सा बना दिया गया है। जबकि 2020 के मूल अभियोग में उनका नाम शामिल नहीं था। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों, यूएन और कई देशों की सरकारों का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उनकी दलीलों की बुनियाद में राज्यसत्ता की सम्प्रभुता है। जबकि ट्रम्प प्रशासन इस आरोप का बचाव एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में करता है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कानून के तहत नार्को-आतंकवादी घोषित एक व्यक्ति को मुकदमे के लिए कठघरे में लाना है। प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सम्प्रभु देश के राष्ट्राध्यक्षों को विदेशी अदालतों में इम्युनिटी प्राप्त होती है।

वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया, उसकी कानूनी वैधता को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को मादुरो की गिरफ्तारी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सैन्य समर्थन देने की तरह बताया है। मादुरो पर 2020 में नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अभियोग लगाया गया था। लेकिन मजे की बात है कि मादुरो की पत्नी सेलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और संशोधित अभियोग का हिस्सा बना दिया गया है। जबकि 2020 के मूल अभियोग में उनका नाम शामिल नहीं था। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों, यूएन और कई देशों की सरकारों का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उनकी दलीलों की बुनियाद में राज्यसत्ता की सम्प्रभुता है। जबकि ट्रम्प प्रशासन इस आरोप का बचाव एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में करता है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कानून के तहत नार्को-आतंकवादी घोषित एक व्यक्ति को मुकदमे के लिए कठघरे में लाना है। प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सम्प्रभु देश के राष्ट्राध्यक्षों को विदेशी अदालतों में इम्युनिटी प्राप्त होती है। स्वयं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1812 में इस विषय पर दिए एक निर्णय में इसे मान्यता दी थी। लेकिन ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि मादुरो वैध राष्ट्रपति नहीं हैं। तथ्य तो यही है कि उन्होंने बार-बार चुनाव जीते हैं और वे अपने देश की राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद द्वारा निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इसलिए चुनावों में धांधली का दावा भी किस अधिकार के बूते किया जा सकता है? दूसरा, और अधिक गंभीर पहलू वेनेजुएला पर कब्जा करके उसके तेल संसाधनों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की अमेरिकी योजना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि उन्होंने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अमेरिकी निर्देशों का पालन करने के लिए मना लिया है। हालांकि इसके बाद रोड्रिगेज ने अमेरिकी कार्रवाइयों की निंदा की। ट्रम्प यह भी कह चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में एक ऑकुपेशन-फोर्स के साथ ही तेल विशेषज्ञों को भी भेज सकता है, ताकि उसके तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। लेकिन किसी देश पर कब्जा करने और उसके संसाधन को वैश्विक बाजार में बेचने के लिए न तो अमेरिकी कानून और न ही अंतरराष्ट्रीय कानून ट्रम्प को कोई कानूनी इजाजत देते हैं। यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2(4) आत्मरक्षा के औचित्य या यूएन की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग करने या इसकी धमकी देने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इन अर्थों में वेनेजुएला पर किया गया हमला यूएन चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

नार्को-तस्करी का आरोप भी केवल इन अवैध अमेरिकी कार्रवाइयों को जायज ठहराने के लिए ही लगाया गया है। वास्तव में, अमेरिका की आधिकारिक नेशनल ड्रग थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में मादुरो के बारे में बहुत कम या लगभग कुछ भी नहीं कहा गया था। इसके विपरीत, इसमें मैक्सिको, कोलंबिया और कुछ अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को मादक पदार्थों के प्रमुख स्रोत के रूप में चिह्नित किया गया था। अमेरिकी कानून के तहत भी इस कार्रवाई की वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन इसे महज एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई बता रहा है। जबकि ऐसी कार्रवाइयों में पूरे नौसैनिक बेड़े, 150 विमानों और हजारों कर्मियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्रम्प तो यह भी संकेत दे चुके हैं कि यदि पहली कार्रवाई विफल होती तो अमेरिका दूसरा और बड़ा हमला करने जा रहा था। यह तो साफ है कि ट्रम्प की नजर वेनेजुएला के 350 अरब बैरल के तेल भंडार पर है। पिछले लगभग बीस वर्षों में, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला का उत्पादन प्रतिदिन 32 लाख बैरल (बीपीडी) के उच्च स्तर से गिरकर मात्र 10 लाख बीपीडी रह गया है। अब ट्रम्प के अनुसार अमेरिका उसके तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में लेगा, उसका पुनर्गठन करेगा और तेल का निर्यात करेगा।

ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि इससे मिलने वाला धन न केवल वेनेजुएला के लोगों के भले के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई भी करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर अमेरिका वास्तव में ही वेनेजुएला के तेल उद्योग का संचालन शुरू कर देता है, तो वहां के लोगों को अपने तेल से मुनाफा मिलने में अभी बहुत समय लगने वाला है। 19वीं-20वीं सदी में अमेरिका ने मैक्सिको, क्यूबा, निकारागुआ, होंडुरास, पनामा पर हमले किए थे। चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, पेरू, ब्राजील में तख्तापलट भी कराए। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल का पुराना अतीत है।

पाकिस्तान को लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं अब बदल रही हैं

> भारत ने दिखाया कि वह परमाणु सीमा में रहते हुए संतुलित सैन्य बल इस्तेमाल करने को तैयार है। इसमें राजनीतिक मंजूरी जल्द मिल जाती है और लक्ष्य भी सीमित होते हैं। संदेश यह था कि आतंकवाद के जवाब में भारत अब महज संयम पर ही निर्भर नहीं रहेगा।उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कौन-से संकेत नहीं दिए। भारत छोटे ऑपरेशन, तय समय सीमा और सैन्य तनाव में बढ़ोतरी के ऐसे तरीकों में नहीं बंधा, जिनका पूवार्नुमान लगाया जा सकता हो। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भविष्य में सैन्य कार्रवाई प्रतीकात्मक या निश्चित अवधि वाली होगी। यह अस्पष्टता भी मायने रखती है। यदि विरोधी पहले ही जान ले कि जवाबी कार्रवाई कैसे, कब और कितनी देर में होगी तो वह उसे अपने आकलन में शामिल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानबूझकर ऐसे सवालों को अनुत्तरित छोड़ा गया था। जब भारत प्रतिक्रिया को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रहा था तो पाकिस्तान के भीतर भी बदलाव चल रहे थे। पाकिस्तानी संविधान में प्रस्तावित 27वां संशोधन महज एक कानूनी बदलाव नहीं है। सेना प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना, सेना के सामूहिक ढांचे को समाप्त करना और परमाणु कमान को पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में लाना- यह बताता है कि सारा नियंत्रण अब शीर्ष पर केंद्रित हो रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह पाकिस्तान के इन संकेतों का जवाब कैसे दे, जिससे तनाव भी ना बढ़े और यह भी नहीं दिखे कि वह चुपचाप बैठा है।

?भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अस्थिरता कायम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों में कोई बड़ी लड़ाई, कूटनीतिक संबंधों में नाटकीय विच्छेद या लंबा सैन्य तनाव नहीं हुआ है, फिर भी रणनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। जो नियम कभी संकट के वक्त लागू होते थे- वे बदल रहे हैं। दोनों देश इस नई वास्तविकता के प्रति खुद को ढाल भी रहे हैं। भारत के लिए वही सवाल आज भी कायम है कि पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा अगली बार बर्दाश्त से बाहर हुई तो हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे? हाल में दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह षड्यंत्र और व्यापक रूप ले सकता था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। ऐसे में उपरोक्त सवाल का जवाब घोषणाओं नहीं, हालिया अनुभवों और पाकिस्तान में हो रहे बदलावों में छिपा है। इसे समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर सबसे अहम संदर्भ है। इसने हमारे माइंडसेट को उजागर किया। भारत ने दिखाया कि वह परमाणु सीमा में रहते हुए संतुलित सैन्य बल इस्तेमाल करने को तैयार है। इसमें राजनीतिक मंजूरी जल्द मिल जाती है और लक्ष्य भी सीमित होते हैं। संदेश यह था कि आतंकवाद के जवाब में भारत अब महज संयम पर ही निर्भर नहीं रहेगा।उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कौन-से संकेत नहीं दिए। भारत छोटे ऑपरेशन, तय समय सीमा और सैन्य तनाव में बढ़ोतरी के ऐसे तरीकों में नहीं बंधा, जिनका पूवार्नुमान लगाया जा सकता हो। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भविष्य में सैन्य कार्रवाई प्रतीकात्मक या निश्चित अवधि वाली होगी। यह अस्पष्टता भी मायने रखती है। यदि विरोधी पहले ही जान ले कि जवाबी कार्रवाई कैसे, कब और कितनी देर में होगी तो वह उसे अपने आकलन में शामिल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानबूझकर ऐसे सवालों को अनुत्तरित छोड़ा गया था। जब भारत प्रतिक्रिया को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रहा था तो पाकिस्तान के भीतर भी बदलाव चल रहे थे। पाकिस्तानी संविधान में प्रस्तावित 27वां संशोधन महज एक कानूनी बदलाव नहीं है। सेना प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना, सेना के सामूहिक ढांचे को समाप्त करना और परमाणु कमान को पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में लाना- यह बताता है कि सारा नियंत्रण अब शीर्ष पर केंद्रित हो रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह पाकिस्तान के इन संकेतों का जवाब कैसे दे, जिससे तनाव भी ना बढ़े और यह भी नहीं दिखे कि वह चुपचाप बैठा है। परमाणु धमकियों के कारण यदि पारंपरिक और मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी रोक दी जाएं तो यह पाकिस्तान की प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति को और प्रभावकारी बनाता है। इसलिए प्रतिरोध का मतलब है कि भारत दिखाए परमाणु हमले की धमकियां उसके विकल्पों पर पूर्ण विराम नहीं लगातीं। इसका मतलब अनावश्यक तनाव बढ़ाना नहीं, कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखना है। कश्मीर इस पूरे बदलाव का केंद्र बना हुआ है। हाल के वर्षों में कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू, खासकर रजौरी, पुंछ और कठुआ में अधिक हिंसा हुई है। यह मायने रखता है। पाकिस्तान का सियासी नैरेटिव और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति जम्मू के बजाय कश्मीर के इर्द-गिर्द घूमती है। घाटी में लंबे समय की शांति उस मुद्दे पर पाकिस्तान की प्रासंगिकता घटाती है, जिसे वह अपनी पहचान का मूल मानता है। पहलगाम हमला इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह किसी सतत अभियान की शुरूआत से ज्यादा ऐसे वक्त में कश्मीर में फिर से मौजूदगी दिखाने का प्रयास लगता है, जब वहां पर्यटन, नागरिक गतिविधियां और सामान्य स्थिति की भावना मजबूत हो रही थी। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान को कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता घटती महसूस हुई, उसने खुले टकराव के बजाय सीमित तौर पर व्यवधान पैदा करने वाली हरकतों का सहारा लिया। स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान रिश्ते किसी जरूरी टकराव की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वे बदली हुई मान्यताओं के तहत संचालित हो रहे हैं। भारत ने बिना कोई सीमा तय किए जवाबी कार्रवाई की इच्छाशक्ति दिखाई है तो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी रणनीति पर निर्भरता समाप्त किए बिना केंद्रीकरण के जरिए ताकत दिखाने का प्रयास किया है। आज पाकिस्तान के प्रतिरोध का मतलब है भारत यह दिखाए कि परमाणु हमले की धमकियां उसके विकल्पों पर पूर्ण विराम नहीं लगातीं। इसका मतलब अनावश्यक तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि कार्रवाई की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना है।

बिना मुकदमे के कैद, लोकतंत्र कहां है

> सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में पांच से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद हैं। हालांकि कोर्ट ने अन्य पांच सह-आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारी की पीठ ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरे देश की नजरें सोमवार के फैसले पर थीं। ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि सभी सात आरोपियों को 5 जनवरी को जमानत मिल जाएगी। लेकिन अदालत ने उमर और शरजील को छोड़कर बाकी को जमानत दे दी।उमर खालिद और शरजील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में वे श्अलग स्थितिश में हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले के शुरूआती सुबूतों से लगता है कि उमर खालिद और शरजील दंगों की योजना और रणनीति बनाने में शामिल थे। ध्यान देने वाली बात ये है कि उमर खालिद पर अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। यानी चाहे जितने भी गंभीर आरोप हों और उसके लिए सबूत हों, अब तक उन्हें पुष्ट करने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। जब मुकदमा चलेगा और फैसला आएगा, तब पता चलेगा कि उमर खालिद दोषी थे या नहीं, लेकिन अभी उन्हें बिना दोषसिद्धि के ही पांच साल से ज्यादा की जेल तो भुगतनी पड़ ही गई है।और ये वो पांच साल हैं, जब व्यक्ति में सबसे अधिक ऊर्जा, रचनात्मकता, सकारात्मकता और सक्रियता होती है। 11 अगस्त 1987 को जन्मे उमर खालिद अभी 38 बरस के ही हैं।

बिना मुकदमे के लंबी कैद लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। इस समय भारत इसी सवाल से दो-चार हो रहा है। यूं तो रोजाना ढेरों प्रसंग ऐसे घटित हो रहे हैं, जिनमें लोकतंत्र को लेकर चिंता उपजती है, ऐसे वक्त में न्यायालय से आए कुछ फैसले आस बंधाते हैं कि सत्ता चाहे अपने स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों से समझौता कर ले, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करेगी। लेकिन सोमवार को उमर खालिद पर आए फैसले ने फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश में लोकतंत्र अब किस हाल में पहुंच गया है।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में पांच से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद हैं। हालांकि कोर्ट ने अन्य पांच सह-आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारी की पीठ ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरे देश की नजरें सोमवार के फैसले पर थीं। ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि सभी सात आरोपियों को 5 जनवरी को जमानत मिल जाएगी। लेकिन अदालत ने उमर और शरजील को छोड़कर बाकी को जमानत दे दी।उमर खालिद और शरजील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में वे श्अलग स्थितिश में हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले के शुरूआती सुबूतों से लगता है कि उमर खालिद और शरजील दंगों की योजना और रणनीति बनाने में शामिल थे। ध्यान देने वाली बात ये है कि उमर खालिद पर अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। यानी चाहे जितने भी गंभीर आरोप हों और उसके लिए सबूत हों, अब तक उन्हें पुष्ट करने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। जब मुकदमा चलेगा और फैसला आएगा, तब पता चलेगा कि उमर खालिद दोषी थे या नहीं, लेकिन अभी उन्हें बिना दोषसिद्धि के ही पांच साल से ज्यादा की जेल तो भुगतनी पड़ ही गई है।और ये वो पांच साल हैं, जब व्यक्ति में सबसे अधिक ऊर्जा, रचनात्मकता, सकारात्मकता और सक्रियता होती है। 11 अगस्त 1987 को जन्मे उमर खालिद अभी 38 बरस के ही हैं। पीएचडी करने के बाद वे अपना भविष्य संवार सकते थे। लेकिन पढ़ने के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने वंचितों के हक में आवाज उठाना जारी रखा, सरकार को परेशान करने वाले सवाल पूछे, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कीं, इस कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और इसके बाद से वो सलाखों में कैद हैं।2020 से कैद उमर खालिद को एक मामले में अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी, दूसरे मामले में उनके खिलाफ अनलॉफुल एंड एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक दो अदालतें उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से लंबित थी, जो अब खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि इस आदेश के एक साल बाद या गवाहों की छानबीन पूरी होने के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम जमानत के लिए फिर से अर्जी दाखिल कर सकते हैं। यानी निकट भविष्य में उमर की रिहाई की संभावनाएं नगण्य दिख रही हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि उमर खालिद के खिलाफ जो सबूत हैं वो काफी कमजोर हैं इसलिए उन्हें जमानत पर बाहर आ जाना चाहिए।लेकिन क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है के बीच ही सारी हकीकत बयां हो जाती है। हो ये रहा है कि बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराया गया था, उसी साल हरियाणा के रोहतक में उसे जेल भेजा गया। तब से लेकर अब तक उसे 15 बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। इस बार मिली पैरोल के दौरान राम रहीम सिरसा में अपने डेरे के मुख्यालय में रहेगा। बता दें कि 2021 के बाद हर साल कम्रीब 90 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली है। अब तक वह 350 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहा है। राम रहीम को अक्सर उसी वक्त पैरोल मिल जाती है, जब चुनावों का वक्त होता है। हरियाणा और दिल्ली के आसपास उसके अनुयायियों की बड़ी संख्या है, उसी का लाभ लेने के लिए शायद उसे किसी न किसी कारण से पैरोल दे दी जाती है। इस मामले में भाजपा पर आरोप भी लगते हैं कि यह सब उसके दबाव में होता है, हालांकि भाजपा नेता बड़ी आसानी से इसे अदालती मामला बताकर टाल जाते हैं। लेकिन यहां मामला केवल कानूनी नहीं नैतिक भी है। क्या भाजपा नेता बलात्कार और हत्या के दोषी को बार-बार की अस्थायी रिहाई से सहमत हैं, अगर ऐसा है तो फिर अपराधियों में कानून का डर किस तरह बैठेगा, ये भी वो बता दें। उमर खालिद पर तो यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों में लगाया जाता है। दिल्ली दंगों की साजिश में उमर का हाथ बताया जाता है, हालांकि उमर इसे झूठा बता चुके हैं और उन्हें तभी गलत साबित किया जा सकेगा, जब मुकदमा चलेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उमर पर मोदी सरकार में आरोप लगे हैं। 2016 में अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने पर उमर खालिद पर राजद्रोह का आरोप लगा। उमर ने जेएनयू छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में भी प्रदर्शन किया और भीमा कोरेगांव हिंसा में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस दर्ज हुआ।

स्टोक्स और लाबुशेन के बीच क्यों हुई थी बहस अब सामने आया पूरा सच

सिडनी। सिडनी टेस्ट में बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन के बीच हुई तीखी बहस पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने खुलासा किया है। ब्रॉड के मुताबिक, लाबुशेन की बातचीत ने उन्हें उनकी लय से बाहर किया और यही इंग्लैंड की रणनीति थी। इसका नतीजा यह रहा कि स्टोक्स ने खुद लाबुशेन को आउट कर दिया। एशेज 2025-26 के पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (रउत्र्) पर बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन के बीच हुई तीखी बहस ने क्रिकेट फैंस का खूब ध्यान खींचा। अब इस पूरे घटनाक्रम पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच आखिर क्या कहा गया था। दूसरे दिन के तीसरे सत्र में बढ़ा तनाव यह घटना टेस्ट के दूसरे दिन के तीसरे और आखिरी सत्र में घटी, जब लाबुशेन ट्रेविस हेड के साथ अच्छी साझेदारी निभा रहे थे। स्टोक्स और लाबुशेन के बीच कुछ तीखी नोकझोंक हुई, जो इतनी बढ़ गई कि कमेंट्री कर रहे मार्क वॉ ने कहा, 'मुझे लगा कि स्टोक्स उन्हें हेडलॉक में ले लेंगे।'

आपकी सीख हमेशा साथ रहेंगी..अर्जुन बिजलानी ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, दिवंगत ससुर से किया ये वादा

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के परिवार पर नए साल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक्टर के ससुर और उनकी पत्नी नेहा के पिता का 1 जनवर को निधन हो गया था, जिसके बाद से अभी भी उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है। वहीं, अर्जुन अपने ससुर के बेहद क्लोज थे और उनकी मौत के गम से उबर नहीं पा रहे हैं। हाल ही ही में उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया है। अर्जुन बिजलानी ने अपने दिवंगत ससुर को याद करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपने परिवार और ससुर के साथ पोज देते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अर्जुन ने लिखा, घ शांति पापा। आप की बातें और सीख हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नेहा और अयान का पूरा ध्यान रखूंगा चिंता मत करना। आपको हमेशा प्यार। बता दें अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, राकेश को अचानक स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वो बच नहीं सके। बता दें, अर्जुन बिजलानी साल के आखिर में अपनी फैमिली संग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दुबई गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ससुर की तबीयत के बारे में जानकारी मिली, वे वेकेशन छोड़ फौरन इंडिया लौट आए और उसके दूसरे ही दिन राकेश चंद्र का निधन हो गया, जिसने एक्टर और उनके पत्नी व बेटे को तोड़ दिया।

एल्विश यादव ही नहीं, सलमान से लेकर एपी ढिल्लों तक ; इन सेलेब्स के घर पर भी हो चुकी है फायरिंग

रविवार के दिन मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं किन सेलेब्स के साथ हाल फिलहाल में फायरिंग के मामले हो चुके हैं। आज 17 अगस्त की सुबह एक घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये घटना यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर हुई, जहां कुछ बदमाशों ने 24-25 राउंड फायरिंग की। हालांकि, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई दिग्गज सितारों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सेलेब्स के साथ फायरिंग का मामला हुआ। जानिए कब और किसके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर में हुई फायरिंग ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। उस दिन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अभिनेता के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हालांकि, आपको बताते चलें कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में कॉमेडियन

मैं खुद को शाबाशी दे रही हूं, प्रियंका चोपड़ा ने 2026 को बताया भविष्य

बोलीं- उम्मीद की किरण जरूरी

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2026 को अपना भविष्य बताया है। साथ ही उन्होंने इस नए साल को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। जानिए एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिका में अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद ले रही हैं। उन्होंने फैमिली के साथ नए साल का स्वागत किया। अब एक्ट्रेस छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने 2026 को अपना भविष्य बताते हुए खुद को भाग्यशाली बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी इस जिंदगी के लिए भी ईश्वर का आभार जताया है। जानिए एक्ट्रेस ने 2026 के लिए अपने क्या विचार साझा किए 2026 में मेरे पहले कुछ कदम प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर कुछ वीडियोज साझा किए हैं। इन वीडियोज में प्रियंका बीच पर नजर आ रही हैं। वीडियोज को बनाते हुए एक्ट्रेस ने 2026 का स्वागत किया और ईश्वर का धन्यवाद जताया। कैप्शन में विचार लिखते हुए एक्ट्रेस वीडियो में कहती हैं, ह्यमैंने खुद से कहा था कि मैं इसमें बेहतर हो जाऊंगी, यानी कैमरे से बात करने में। 2026 में मेरे पहले कुछ कदम। यह भविष्य जैसा लगता है। मैं अपने प्रशंसकों से कहती रही हूं कि 2026 भविष्य जैसा लगता है। यह कैसे संभव है? लेकिन हम यहां हैं, अपने परिवार को देख रही हूं, अपने खूबसूरत कदमों को देख रही हूं और खुद को भाग्यशाली मानकर आभारी हूं। इतने लंबे समय तक इतनी तेज गति से दौड़ने के बाद, आप खुद को शाबाशी देना भूल जाते हैं कि आप बच गए। तो मैं खुद को शाबाशी दे रही हूं। इस जीवन को जीने के लिए आभारी हूं

प्रियंका ने स्टोरी पर एक और वीडियो भी साझा किया। दूसरे वीडियो में अपनी बात को जारी रखते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि खुद के प्रति दयालु रहना और इस जीवन को जीने का मौका मिलने के लिए वास्तव में मैं आभारी हूं। हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर होती है। बस आगे बढ़ते रहो। अब मैं अपने घर की ओर पीछे की ओर चल रही हूं।

वाराणसी में नजर आएंगी प्रियंका

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा हाल ही में कपिल शर्मा के शो ह्यद ग्रेट इंडियन कपिल शो के पहले एपिसोड में नजर आई थीं। इसके अलावा वो अब एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में दिखाई देंगी। बड़े स्तर पर बन रही इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होनी है।

मुंबई की जहरीली हवा में हिना खान का सांस लेना हुआ मुश्किल

भड़ास निकालते हुए बोलीं-सुबह से ही हालत बहुत खराब

दिल्ली के बाद मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। लगातार हवा की गिरती क्वालिटी के साथ जन-जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है। मुंबई में हवा की इस भयानक स्थिति पर हिना खान ने चिंता जताई है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह बढ़ते पॉल्यूशन की समस्या से परेशान हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें मुंबई में लेटेस्ट एक्यूआई 209 दर्ज किया गया। इस स्टोरी के साथ एक्ट्रेस ने लिखा-क्या हो रहा है? सांस नहीं ले पा रही हूं। बाहर जाना कम कर दिया है। लगातार खांसी हो रही है। सुबह से ही हालत बहुत खराब है। हिना खान ने बताया ,ब्रेस्ट कैंसर से जूझने के कारण यह मेरे लिए और भी चौलेंजिंग है। प्रदूषित हवा की वजह से मेरा बाहर निकलना और शारीरिक तौर पर कोई काम करना भी सीमित हो गया है। यह मेरे जीवन की गतिविधियों पर भी असर डाल रहा है।

बता दें, इससे पहले हिना खान ने एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट ऑल अबाउट हर में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी कैंसर जर्नी के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि उनका इलाज कठिन रहा और इस दौरान उन्हें अच्छे और बुरे दोनों दिन देखने को मिले। उन्होंने हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी ली, और कीमो के पहले हफ्ते में उन्हें बहुत दर्द होता था, लेकिन बाकी के दो हफ्ते, वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती थीं और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ वक्त बिताती थीं। एक्ट्रेस ने आगे कहा-देखने का नजरिया बहुत जरुरी है।

लव फिल्म्स ने वध 2 का दमदार नया पोस्टर किया जारी, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता आए नजर

थिएटर में रिलीज होने में अब सिर्फ एक महीना बाकी है और वध 2 को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच लव फिल्म्स ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता वाला एक दमदार नया पोस्टर रिलीज किया है। 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म एक मजबूत और अपने साथ बांधे रखने वाली कहानी का वादा करती है, जो सोच, नैतिकता और सच की नाजुक परतों को गहराई से छूती है। नए पोस्टर में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक शांत और सोच में डूबे हुए पल में नजर आ रहे हैं। उनकी गंभीर और ठहरी हुई मौजूदगी इशारा करती है कि कहानी कई नजरियों से बनी है, जहां सच एक जैसा नहीं बल्कि परतों में छिपा है। यह पोस्टर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि नजरिया, इरादा और विश्वास कैसे बदलते हैं। जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित वध 2 में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म एक नई कहानी लेकर आती है, लेकिन वध की वही भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली गहराई बरकरार रखती है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। वध 2 को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है, खासकर 56वें आईएफएफआई 2025 में जब फिल्म का गाला प्रीमियर हाउसफुल शो में हुआ। स्क्रीनिंग के बाद लंबे समय तक तालियां बजती रहीं और फिल्म को खूब सराहना मिली। इस मौके ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और भरोसेमंद कलाकारों में से हैं। लव फिल्म्स के बैनर तले बनी वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

दीपिका ने फैंस के साथ मनाया जन्मदिन, दिए कीमती तोहफे;

जानिए गिफ्ट्स से लेकर खाने के मेन्यू तक में क्या कुछ था?

विदेश में अपना जन्मदिन मनाने से पहले दीपिका ने मुंबई में एक फैन मीट रखी। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने प्रशंसकों को कीमती तोहफे भी दिए। जानिए इन तोहफों में क्या कुछ था बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बीते सोमवार को अपना 40वां जन्मदिन मनाया। दीपिका ने अपना जन्मदिन पति और अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में मनाया। लेकिन विदेश जाने से पहले उन्होंने अपने फैंस के लिए मुंबई में एक फैन मीट का आयोजन किया। इसमें उन्होंने देश भर से अपने फैंस को आभार व्यक्त करने और एक-दूसरे से जुड़ने के लिए इनवाइट किया। इस दौरान एक्ट्रेस ने उनके हवाई जहाज का किराया भी खुद ही दिया और उन्हें एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक भी खुद से ही बुलवाया। इस दौरान दीपिका ने फैंस को जो उपहार दिए, उनमें क्या था इसका भी पता चला है। जानिए दीपिका ने अपने फैंस को क्या गिफ्ट्स दिए दीपिका ने इस तरह किया स्वागत इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे फैंस को उनकी कारों में वेलकम बास्केट भी दिए गए, जिनमें कुछ गिफ्ट्स थे। अब दीपिका के फैंस ने अपनी पसंदीदा कलाकार का आभार जताते हुए तस्वीरें और वीडियोज साझा किए हैं। इनमें उन बास्केट की फोटोज भी हैं, जिनमें उन्हें गिफ्ट्स मिला था। तस्वीरों से पता चलता है कि इन बास्केट में मेवा, ओआरएस टेट्रा पैक और नारियल पानी जैसी चीजें शामिल थीं। हर एक बास्केट में 'अ डे ऑफ ग्रेटीट्यूड विद दीपिका पादुकोण' टाइटल से एक लेटर भी था। इसमें लिखा था, ह्यसमय निकालने और आज की यात्रा करने के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद है। खाने के मेन्यू में थे कई आइटम यह कार्यक्रम एक निजी समारोह के तौर पर हुआ। इसमें खाने के मेन्यू में चिकन और मछली से लेकर पनीर की थालियों और पेस्ट्री तक कई तरह के व्यंजनों से भरपूर एक शानदार बुफे था। नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स और मॉकटेल भी मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल को लाल, मैरून और सुनहरे रंगों से सजाया गया था, जिसमें क्रिसमस ट्री और थीम से संबंधित सजावटी सामान भी शामिल थे। प्रशंसकों के दीपिका के लिए कुछ लिखने के लिए एक फैन वॉल बनाई गई थी। दीपिका ने फैंस को दिए कीमती तोहफे इस दौरान दीपिका की ओर से हर फैन को एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर भी दिया गया था। जिसका वजन कथित तौर पर पांच किलोग्राम बताया जा रहा है और जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये बताई जा रही है। हैम्पर में वेटेड ब्लैंकेट, ब्रांडेड सिल्क आई मास्क, एर्गोनॉमिक पिलो और दीपिका के स्किनकेयर ब्रांड के प्रोडेक्ट्स शामिल थे। इनमें क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन शामिल थे। दीपिका ने प्रत्येक फैन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके हाथों से लिखे हुए मैसेज भी पढ़े। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने अब इस मुलाकात के वीडियोज साझा किए हैं। इनमें दीपिका को जन्मदिन का केक काटते हुए देखा जा सकता है। साथ ही फैंस 'आंखों में तेरी अजब सी अदाएं' गाना गा रहे हैं। इस मौके पर दीपिका ने कई मुद्दों पर बात भी की।

देवदत्त पडिक्कल का विजय हजारे ट्रॉफी में कीर्तिमान 600+ रन पूरे करते ही हासिल की उपलब्धि

नई दिल्ली। शानदार फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। पडिक्कल इस टूनार्मेंट के तीन अलग सत्र में 600+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। पडिक्कल ने कर्नाटक के लिए खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। पडिक्कल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया। पडिक्कल ने मौजूदा टूनार्मेंट में 600+ रन पूरे कर लिए हैं और वह पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के तीन अलग-अलग सत्र में इतने रन बनाए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार रहा है पडिक्कल का सफर विजय हजारे ट्रॉफी में पडिक्कल का सफर शानदार रहा है। उन्होंने 2019-20 सत्र में 11 मैचों मे 609 रन बनाए थे और वह उस सीजन टूनार्मेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इसके बाद 2020-21 सत्र में पडिक्कल ने दमदार प्रदर्शन किया था और सात मैचों में 147.40 के औसत से 737 रन बनाए थे जिसमें चार शतक भी शामिल थे। उस सत्र में कर्नाटक की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही थी।

डेनमार्क को वेनेजुएला समझने की कोशिश न करे ट्रंप मेटे फ्रेडरिक्सन की अमेरिकी राष्ट्रपति को दो टूक

कोपेनहेगन। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का मतलब नाटो मिलिट्री गठबंधन का खत्म होना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को करारा हमला बोला और उन्होंने कहा कि डेनमार्क को अमेरिका वेनेजुएला समझने की कोशिश न करे। हम पर हमला करना नाटो मिलिट्री गठबंधन का अंत होगा। वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में है। उनके इस बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को तीखा पलटवार किया और कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नाटो मिलिट्री गठबंधन का अंत होगा। बता दें कि काराकास में अमेरिकी सेना द्वारा नेता निकोलस

मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के लिए आधी रात को किए गए ऑपरेशन से पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका के इस कदम से डेनमार्क और ग्रीनलैंड की चिंता बढ़ गई, जो डेनिश साम्राज्य का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है और इस तरह नाटो का हिस्सा है। फ्रेडरिकसेन ने सोमवार को डेनिश ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की और विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ₹अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर मिलिट्री हमला करने का फैसला करता है, तो सब कुछ रुक जाएगा। यानी, हमारे नाटो और इस तरह दूसरी दुनिया की जंग खत्म होने के बाद से मिली सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। 20 दिन की टाइमलाइन से डर और बढ़ गया है ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति बनने के दौरान और अपने दूसरे कार्यकाल के शुरूआती महीनों में बार-बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका के अधिकार की बात कही, और उन्होंने द्वीप पर कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने से भी इनकार नहीं किया है। रविवार को उनकी टिप्पणियों, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, ह्यआइए 20 दिनों में ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैंह्ल ने इस डर को और बढ़ा दिया कि अमेरिका भविष्य में ग्रीनलैंड में दखल देने की योजना बना रहा है। फ्रेडरिकसेन ने यह भी कहा कि जब ट्रंप कहते हैं कि वह ग्रीनलैंड चाहते हैं, तो उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ₹हम ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे जहां हमें और ग्रीनलैंड को इस तरह से धमकी दी जाए।₹ ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती: नीलसन नीलसन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती है। उन्होंने अपने समर्थकों से शांत और एकजुट रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, 'हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां हमें लगता है कि रातों-रात देश पर कब्जा हो सकता है और इसीलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अच्छा सहयोग चाहते हैं।' नीलसन ने आगे कहा, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका आसानी से ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। वहीं, डेनिश ब्रॉडकास्टर के राजनीतिक पत्रकार आस्क रोस्ट्रुप ने सोमवार को स्टेशन के लाइव ब्लॉग पर लिखा कि मेटे ने पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के विचार को साफ तौर पर खारिज कर दिया होता। लेकिन अब बयानबाजी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें इस संभावना को मानना पड़ रहा है।

उस्मान हादी के समर्थन में निकली रैली प्रदर्शनकारियों की भारतीयों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग

बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्यारों को पकड़ने और सजा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को उनके समर्थकों ने मार्च निकाला। इंकलाब मंचो के प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को ढाका में उनकी पार्टी ने एक दिवसीय रैली का आयोजन किया। इस रैली में बांग्लादेश में रहने वाले सभी भारतीयों के वर्क परमिट रद्द करने की भी मांग की। कई चौराहों से गुजरा मार्च अखबार ने आयोजकों के हवाले से बताया कि 'न्याय के लिए मार्च' सुबह करीब 11:30 बजे शाहबाग से शुरू हुआ, जिसमें

कार्यकर्ता 10 पिकअप वैन में और पैदल चलकर साइंस लैब, मोहम्मदपुर, मीरपुर-10, उत्तरा, बसुंधरा, बड्डा, रामपुरा और जात्राबारी सहित कई प्रमुख चौराहों से गुजरे और शाम को शाहबाग लौट आए। प्रतिभागियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य हादी की हत्या की जांच में ₹प्रगति की कमी₹ की ओर ध्यान आकर्षित करना था, और मांग की कि हत्यारे, योजनाकारों, सहयोगियों और उन्हें शरण देने वालों सहित सभी संबंधित लोगों को 12 फरवरी के संसदीय चुनावों से पहले मुकदमे के लिए लाया जाए। मार्च में कई नारे लगे मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ₹हम हादी के खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे,₹ ₹मेरा भाई कब्र में पड़ा है जबकि हत्यारा आजाद क्यों है?₹ और ₹लाल और हरा झंडा, इंकलाब का झंडा - आप हादी को देख सकते हैं₹ जैसे नारे लगाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि सेना खुफिया महानिदेशालय के भीतर कथित फासीवादी सहयोगियों की पहचान की जाए। उन्हें गिरफ्तार किया जाए और न्याय के कटघरे में लाया जाए। हादी एक बांग्लादेश के युवा नेता थे बता दें कि 32 वर्षीय हादी, जो एक प्रमुख युवा नेता थे और जुलाई-अगस्त 2024 के जन विरोध प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए थे, जिसके कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी, को 12 दिसंबर को ढाका में एक चुनावी अभियान के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। वह आगामी 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों में भी उम्मीदवार थे। हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन 18 दिसंबर को उनका निधन हो गया।

ट्रंप हुए वेनेजुएला में व्यस्त पेरिस में यूक्रेन के सहयोगी देशों की शांति वार्ता अधर में लटकी

पेरिस। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि संभावित यूरोपीय सैन्य तैनाती में अभी भी कई बाधाएं हैं। महत्वपूर्ण विवरण को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और सेना भेजने के लिए हर कोई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता देने पर भी कई देशों को संसद की मंजूरी लेनी होगी। रूस के साथ संभावित युद्धविराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा तय करने में मदद करने वाली महत्वपूर्ण वार्ता के लिए सहयोगी देश मंगलवार को पेरिस में मिल रहे हैं। हालांकि, ट्रंप प्रशासन का ध्यान वेनेजुएला की ओर होने के चलते प्रगति की संभावना अनिश्चित है। अमेरिका के वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कथित 'इच्छुक देशों के गठबंधन' की नई बैठक के बारे में आशा जताई थी। ये देश कई महीनों से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन से लड़ना बंद करने पर सहमत हो जाता है, तो भविष्य में किसी भी रूसी आक्रमण को कैसे रोका जाए। अमेरिका का प्रतिनिधित्व ट्रंप नहीं, ये अधिकारी करेंगे 31 दिसंबर को अपने संबोधन में मैक्रों ने कहा कि सहयोगी देश शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की रक्षा करने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। मैक्रों के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी निजी तौर पर मौजूद होंगे, जिनमें 27 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों सहित 35 प्रतिभागी शामिल हैं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शुरू में विदेश मंत्री मार्को रुबियो करने वाले थे, जिन्होंने वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप से संबंधित कारणों से अपनी योजना बदल दी। युद्धविराम नहीं, यूक्रेन खोज रहा समाधान की राह युद्ध खत्म होने के बाद प्रतिभागी पांच प्रमुख प्राथमिकताओं पर ठोस नतीजा चाहते हैं। इनमें युद्धविराम की निगरानी के तरीके, यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए समर्थन, भूमि-समुद्र-हवा में एक बहुराष्ट्रीय बल की तैनाती, रूस की ओर से एक और आक्रमण की स्थिति में प्रतिबद्धताओं के इतर यूक्रेन के साथ दीर्घकालिक रक्षा सहयोग शामिल है। हालांकि, मंगलवार को होने वाली बैठक में यह संभव हो पाएगा या नहीं, यह अब स्पष्ट नहीं है। दरअसल, ट्रंप वेनेजुएला में नेतृत्व परिवर्तन करने के अपने फैसले के बाद के उसके नतीजों से निपटने में मशगूल हैं। यूक्रेन वॉशिंगटन से सैन्य और अन्य प्रकार की सहायता की ठोस गारंटी चाहता है, जिसे वह अन्य सहयोगियों से इसी तरह की प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। कीव किसी भी युद्धविराम को लेकर सतर्क है, क्योंकि उसे डर है कि इससे रूस को फिर से संगठित होने और दोबारा हमला करने का समय मिल सकता है।

मुझे नहीं दिखता कार्रवाई का खतरा ट्रंप की धमकी के बाद मेक्सिको की राष्ट्रपति शीनबाम का बड़ा बयान

मेक्सिको। मेक्सिको के सुरक्षा विश्लेषक डेविड सॉसेडो ने कहा कि यह धमकी मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाने की धमकियों की तरह (जिनमें से कुछ लागू की गईं और कुछ नहीं), व्यापारिक, राजनयिक और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए एक समझौते का हथियार रही है। उन्होंने कहा कि रूबियो और ट्रंप 'अच्छे पुलिस वाले, बुरे पुलिस वाले' की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें ट्रंप धमकी देते हैं और रूबियो मामले को सुलझाते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद कई देशों पर इसी तरह की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इस बीच मेक्सिकन सरकार और विश्लेषकों ने मेक्सिकन ड्रग कार्टेल के खिलाफ एकतरफा अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम का प्रशासन वॉशिंगटन की मांगों का पालन कर रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध

महत्वपूर्ण हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि मेक्सिको से और अधिक रियायतें हासिल करने के लिए इस तरह की और धमकियां दी जाएंगी। 'मुझे नहीं दिखता कोई जोखिम', बोलीं शीनबाम हालांकि, ट्रंप की ओर से कोई अप्रत्याशित कदम उठाने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच सोमवार को शीनबाम ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना को कम करके आंका। उन्होंने कहा, 'मुझे इसमें कोई जोखिम नहीं दिखता। अमेरिका सरकार के साथ समन्वय और सहयोग है।' उन्होंने कहा, 'मुझे हमले की संभावना पर विश्वास नहीं है, मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से संगठित अपराध का समाधान नहीं होता।' मेक्सिको क्यों नहीं है वेनेजुएला? दरअसल, मेक्सिको की स्थिति वेनेजुएला या अमेरिका की धमकियों की जद में आए क्यूबा जैसे देशों से बिल्कुल अलग है। पहली बात तो यह है कि शीनबाम एक लोकप्रिय और वैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। दूसरा मेक्सिको अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। एक ऐसा देश जहां 4 करोड़ मेक्सिकन रहते हैं। तीसरा अमेरिका में पूर्व मेक्सिकन राजदूत मार्था बासेर्ना ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मेक्सिको के साथ उच्च स्तरीय सहयोग को स्वीकार किया है। ट्रंप की धमकियां क्या दबाव बनाने की रणनीति? ट्रंप और उनके सहयोगियों ने अपने चुनाव अभियान के बाद से ही मेक्सिको में कार्टेल पर हमला करने के बयान दिए लेकिन उनका लहजा पहले से कहीं ज्यादा संयमित दिखा है। शीनबाम ने पुष्टि की है कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में मेक्सिको में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का मामला बार-बार उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। वह इसे एक असंभव प्रस्ताव मानती हैं और जोर देकर कहती हैं कि ट्रंप के साथ उनका रिश्ता आपसी सम्मान पर आधारित है।

मानवाधिकार या अपने हितों की राजनीति इराक-लीबिया से वेनेजुएला तक अमेरिका की दखल रणनीति का पूरा सच

नेटवर्क। वेनेजुएला संकट ने एक बार फिर अमेरिका की वैश्विक सैन्य दखल नीति पर बहस तेज कर दी है। इराक में रासायनिक हथियार, अफगानिस्तान में आतंकवाद, लीबिया में नागरिक सुरक्षा और वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली जैसे दावों के पीछे ऊर्जा संसाधनों, भू-राजनीतिक वर्चस्व और रणनीतिक नियंत्रण के हित छिपे रहे। रिपोर्टें बताती हैं कि मानवीय तर्क अक्सर रणनीतिक स्वार्थों का आवरण रहे हैं। वेनेजुएला संकट के बाद यह सवाल फिर नए सिरे से खड़ा हो गया है कि अमेरिका अपनी वैश्विक सैन्य और रणनीतिक दखलअंदाजी को अक्सर लोकतंत्र, मानवाधिकार और सुरक्षा के नाम पर सही ठहराता रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सामरिक संस्थानों और प्रतिष्ठित मीडिया की रिपोर्टें बताती हैं कि इन हस्तक्षेपों के पीछे ऊर्जा संसाधन, भू-राजनीतिक वर्चस्व और रणनीतिक नियंत्रण जैसी ठोस स्वार्थ-संचालित प्राथमिकताएं भी रहीं। इराक में रासायनिक हथियार, अफगानिस्तान में आतंकवाद, लीबिया में नागरिक सुरक्षा और वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली तथा ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई, जैसे दावों पर रैंड कॉरपोरेशन, ब्राउन यूनिवर्सिटी, चैथम हाउस और सिप्री जैसे संस्थानों की रिपोर्ट साफ तौर पर इशारा करती हैं कि अमेरिका अपने निहित स्वार्थों के लिए समय-समय पर रणनीतिक कदम उठाता रहा है। इराक में रासायनिक हथियार का दावा, लेकिन सच्चाई कुछ और रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में रासायनिक हथियार का दावा किया गया था लेकिन रणनीतिक सच्चाई अलग थी। 2003 में अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हमला किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक व बायोलॉजिकल हथियार हैं। हालांकि दूसरी ओर यूएस सीनेट इंटैलिजेंस कमेटी और बाद में प्रकाशित ड्यूल्फर रिपोर्ट (यूएस सरकार द्वारा नियुक्त जांच) ने स्पष्ट किया कि ऐसे हथियार नहीं मिले। दरअसल अमेरिका यहां के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता था। वियतनाम में सैन्य शक्ति के बावजूद ऐतिहासिक हार वियतनाम युद्ध अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाता है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और अकादमिक अध्ययनों के अनुसार भारी सैन्य ताकत के बावजूद अमेरिका उत्तर वियतनाम को रोक नहीं पाया और 1975 में पीछे हटना पड़ा। आज भी रैंड कॉरपोरेशन वियतनाम को रणनीतिक चेतावनी के रूप में उद्धृत करता है। इराक में मौजूदगी से तेल की वैश्विक आपूर्ति में बना रहा अमेरिकी दबदबा यूएस एनर्जी इन्फर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) और रैंड कॉरपोरेशन के आकलन के अनुसार इराक दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों वाले देशों में है और वहां अमेरिकी सैन्य-राजनीतिक मौजूदगी ने वैश्विक तेल आपूर्ति को पश्चिमी प्रभाव-क्षेत्र में बनाए रखने में मदद की। युद्ध के बाद इराकी तेल क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुले, जिनमें अमेरिकी और पश्चिमी ऊर्जा कंपनियों को उत्पादन-साझेदारी, तकनीकी सेवाओं और सुरक्षा-समर्थित अनुबंधों में हिस्सेदारी मिली। इससे अमेरिका को वैश्विक तेल बाजार में कीमतों और आपूर्ति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, मध्य-पूर्व में ऊर्जा मार्गों पर रणनीतिक पकड़ और चीन-रूस जैसे प्रतिस्पर्धियों की स्वतंत्र पहुंच को सीमित करने का लाभ मिला। अफगानिस्तान-सबसे लंबा युद्ध, अंततः वापसी 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू की। उद्देश्य था अल-कायदा का खात्मा और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था। बीस वर्षों की मौजूदगी के बावजूद 2021 में अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान सत्ता में लौट आया। ब्राउन यूनिवर्सिटी के अनुसार यह अमेरिका की रणनीतिक विफलता थी, जहां घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हुए।

मादुरों को हटाने से पहले कब-कब अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल भंडार को लेकर दबाव बनाया

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में कोई कार्यवाई की है। बल्की यह विवाद दशकों पुराना है। पहले यहां के तेल में अमेरिकी कंपनियों का बहुत दखल था। लेकिन 1976 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह दखल कम हुआ। जिसे आज तक अमेरिका वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को बंधक बना लिया। यह हमला वेनेजुएला की तरफ से अचानक नहीं किया गया है बल्कि, अमेरिका कई समय से अलग अलग तरीके से इसकी तैयारी कर रहा था। हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका वेनेजुएला को ह्यचलाएगाह्ल, इसके साथ उनके तेल को भी संसाधित करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के खराब हो चुके तेल उद्योग को नया करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने को तैयार है। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल का तेल भंडार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल और सऊदी अरब से भी ज्यादा है। यह वैश्विक भंडार का लगभग 20 प्रतिशत है। वेनेजुएला में ट्रंप प्रशासन की सैन्य कार्रवाई कई मायनों में अभूतपूर्व थी। लेकिन वेनेजुएला के तेल भंडार और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज और मदुरो के साथ अमेरिका के जिस तरह के संबंध थे, उसे देखते हुए यह हैरान करने वाला नहीं था । अमेरिकी निवेश का बढ़ना और फिर खत्म होना वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। यहां की आबादी लगभग 30 अरब है। यह कैलिफोर्निया से लगभग दोगुना है। 20वीं सदी की शुरू में तेल भंडार के कारण यह दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश थी। अमेरिकी कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल के विकास में भारी निवेश किया। देश की राजनीति में भी उनका बड़ा हाथ था। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार को खुद नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन मना करने के बावजूद वहां के नेताओं ने मुख्य निर्यात संसाधन को नियंत्रित करना शुरू किया। 1960 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (डढएउ) का गठन हुआ। इसमें वेनेजुएला प्रमुख देश बना और 1976 में अपने अधिकांश तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका अमेरिका की कंपनियों पर बुरा असर पड़ा। इसने ट्रंप प्रशासन के हाल के दावों को हवा दी कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल ₹चुरायाह्ल है। इस राष्ट्रीयकरण के बाद वेनेजुएला को आर्थिक तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ। तेल उद्योग के कुप्रबंधन के कारण 1988 में कर्ज संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हस्तक्षेप हुआ। फरवरी 1989 में काराकास में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, और सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेज दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित 300 लोग मारे गए। इसके बाद वेनेजुएला के लोग दो वर्गों में बंट गया। अमीर लोग अमेरिका के साथ काम करना चाहते थे। वहीं मजदूर वर्ग अमेरिका से आजादी चाहता था। इस बंटवारे ने तब से वेनेजुएला की राजनीति को परिभाषित किया है। शावेज का सत्ता में आना और गरीबों के लिए काम करना ह्यूगो शावेज देश के राष्ट्रपति बनने से पहले मिलिट्री ऑफिसर थे। 1980 के दशक में उन्होंने सेना के अंदर समाजवादी गुट बनाया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जोशीले भाषण देना शुरू किया। 1989 में सरकार विरोधी दंगो के बाद उन्होंने सरकार गिराने की योजना बनाना शुरू कर दिया। फरवरी 1992 में अमेरिका का समर्थन करने वाले राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेज को हटाने की असफल कोशिश की। शावेज को दो साल के लिए जेल हुई, लेकिन 1998 में वह एक समाजवादी क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर उभरे। शावेज वेनेजुएला और लैटिन अमेरिकी राजनीति दोनों में एक बड़ी हस्ती बन गए। शावेज न सिर्फ वेनेजुएला में तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल खाने, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकारी कार्यक्रमों को सब्सिडी देने के लिए जाने जाते थे। शावेज ने क्यूबा को अरबों डॉलर का तेल दिया, जिसके बदले में हजारों क्यूबा के डॉक्टर वेनेजुएला के हेल्थ क्लीनिक में काम करते थे।

लेबनान के कई इलाकों में इस्त्राइल का ड्रोन हमला निरस्त्रीकरण बैठक से पहले हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई

सीदोन। लेबनानी सरकार गुरुवार को एक बैठक में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने वाली है, जिसमें सेना कमांडर जनरल रुडोल्फ हायकल भी शामिल होंगे। सोमवार को हुए हवाई हमले लिटानी नदी के उत्तर में स्थित गांवों में हुए जो इस्त्राइल की सीमा से काफी दूर हैं। इस्त्राइल की वायुसेना ने मंगलवार लड़के दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों पर हमला किया, जिसमें देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर सीदोन भी शामिल है। मंगलवार तड़के करीब एक बजे हुए हमले में दक्षिणी तटीय शहर सीदोन में एक तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत ध्वस्त हो गई। यह घटना लेबनान के सेना कमांडर की ओर से इस्त्राइल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के अपने मिशन पर सरकार को जानकारी देने से कुछ दिन पहले हुई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं घटनास्थल पर मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटोग्राफर ने बताया कि यह इलाका एक व्यावसायिक जिले में था, जिसमें वर्कशॉप और मैकेनिक की दुकानें थीं और इमारत में कोई नहीं रहता था। इस हमले के बाद कम से कम एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बचाव दल घटनास्थल पर अन्य लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन तत्काल किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई। वहीं, सोमवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में कई ठिकानों पर हमला किया। उनका कहना था कि इन ठिकानों पर हिज्बुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूहों का बुनियादी ढांचा मौजूद था। ये हमले इस्त्राइल के सैन्य प्रवक्ता अविचाई अद्रई की ओर से एक्स पर चेतावनी पोस्ट करने के लगभग दो घंटे बाद हुए। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि सेना पूर्वी बेका घाटी के दो गांवों और दक्षिणी लेबनान के दो अन्य गांवों में हिज्बुल्लाह और फिलिस्तीनी हमास समूहों के ठिकानों पर हमला करेगी। सीदोन में हुआ बाद का हमला बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया था और इस्त्राइली सेना ने इस पर तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया। एक दिन पहले भी किए थे ड्रोन हमले लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि बेका घाटी के मनारा गांव में जिस घर पर हमला हुआ

सुलावेसी प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ 16 लोगों की मौत

मनाडो। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो गई और कई गांव जलमग्न हो गए। तेज बहाव से घर बह गए, सैकड़ों लोग बेघर हुए और पुलिस-सेना की मदद से बचाव दल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो गई।अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया कि कई दिनों से जारी मानसूनी बारिश के बाद सोमवार सुबह नदियां उफान पर आ गईं। प्रभावित गांवों में भेजे गए बचाव दल इसी के बाद कीचड़, पत्थरों और मलबे से भरा तेज बहाव सिआउ तागुलंदांग बियारो जिले में लोगों को बहा ले गया और कई गांव पानी में डूब गए। पुलिस और सेना की मदद से आपातकालीन बचाव दलों को सिआउ द्वीप के बुरी तरह प्रभावित चार गांवों में भेजा गया। यह छोटा सा द्वीप सुलावेसी द्वीप के उत्तरी छोर से करीब 130 किलोमीटर दूर है। मुहारी ने बताया कि कई जगह सड़कों के टूटने और संचार व्यवस्था बाधित होने से पहुंचने में मुश्किलें आईं। सात घर बहे और 140 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त उन्होंने कहा कि पहाड़ियों से पानी के तेज बहाव के कारण सात घर पूरी तरह बह गए और 140 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ के चलते 680 से अधिक लोगों को चर्चों और सार्वजनिक इमारतों में बने अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। बचावकर्मियों ने बरामद किए 16 शव मौसम में सुधार और बाढ़ का पानी उतरने के बाद मंगलवार को बचावकर्मियों ने 16 शव बरामद किए। उत्तरी सुलावेसी खोज एवं बचाव कार्यालय के प्रवक्ता नूरियादियन गुमेलेंग ने बताया कि तीन अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है, जहां पूरे के पूरे इलाके पानी में डूब गए थे। सिटारो जिले की प्रमुख चिंतिया इंग्रिड कालांगित ने सोमवार से 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है, ताकि राहत सामग्री पहुंचाने, लोगों को सुरक्षित निकालने और बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम तेजी से किया जा सके। इस बाढ़ में 25 लोग घायल भी हुए हैं। कालांगित ने कहा, हमने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि आगे और बारिश होने से फिर बाढ़ या भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : RNI-MPHIN/2023/88414 देवांश प्रिंटिंग प्रेस 12/12 विनय नगर सेक्टर-2 ग्वलियर(म.प्र.) से मुद्रित एंव 433 आनंन नगर डबल रोड बहोड़ा ग्वालियर से प्रकाशित एवं सम्पादित।
E-Mail : mantragwalior@gmail.com । सम्पादक : मनीष शुक्ला, मोबाइल : 7007837917 स्थानीय संपादक- आनंद त्रिवेदी । वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र ग्वालियर न्यायालय होगा।